RIN No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : भोपाल/म.प्र./581/2021-2023
Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश
वर्ष 21 अंक 12 05 अगस्त 2021

जगत विज़न

राजनीतिक संग्राम में बदला पेगासस जासूसी विवाद

पेगासस जासूसी कांड

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
मध्यप्रदेश संवाददाता	अर्चना शर्मा
राजनीतिक संवाददाता	समीर शास्त्री
विशेष संवाददाता	बिन्देश्वरी पटेल
छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ	मणिशंकर पाण्डेय
छत्तीसगढ़ संवाददाता	आनन्द मोहन श्रीवास्तव,
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय
गोवा ब्यूरो चीफ	अजय सिंह
गुजरात ब्यूरो चीफ	गौरव सेठी
दिल्ली ब्यूरो चीफ	विजय वर्मा
पटना संवाददाता	सौरभ कुमार
उत्तरप्रदेश ब्यूरो चीफ	वेद कुमार
बुंदेलखण्ड संवाददाता	रफत खान
विधिक सलाहकार	एडवोकेट राजेश कुंसारिया

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल

मो. 98260-64596, मो. 9893014600

फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com

Website: www.jagatvision.in

राजनीतिक संग्राम में बदला पेगासस जासूसी विवाद

(पृष्ठ क्र.-6)

- पहले हमला, फिर आरोप, उसके बाद हंगामा 30
- दांव पर यरूशलम 36
- नवजोत सिंह सिद्धू को मिली पंजाब कांग्रेस की कमान 40
- पायलट और गहलोत का स्कोर कार्ड और भविष्य 43
- टीकारण: कथनी और करनी में फर्क 46
- पर्यावरण सुरक्षा को बनायें नागरिक धर्म 48
- सड़के होगी आत्म निर्भर 50
- सरोगेसी का कारोबार 30 अरब रूपये सालाना से ज्यादा 52
- कोरोना की तीसरी लहर आई है 54
- दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा का गहराता संकट 56
- अश्लीलता के कारोबार में फिल्मी हस्तियां..... 60

भारत के 40 से ज्यादा पत्रकारों की जासूसी
PRESS
उम्मीद है, अब लोग हमें पसंद करने लगें...
पेगासस

राज्यों में मची सियासत की उठापटक

वर्तमान में भारत का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। हर कोई अपनी सत्ता चमकाने में लगा हुआ है। ऐसे में अगले साल कई राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले ही राजनीतिक मुद्दे उठाए जाने लगे हैं। बता दें कि इसमें देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की सबसे अहम भूमिका है। कांग्रेस अपनी पहचान फिर से बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है और भी कांग्रेस कई बड़े फैसले ले रही है। कर्नाटक में बी.एस. येदियुरप्पा सीएम पद से इस्ती फा दे चुके हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवागत प्रदेश कांग्रेस अध्येक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तनातनी बरकरार है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच भी माहौल गर्म है। तीनों रायों में इन दिनों काफी राजनीतिक हलचल मची हुई है। जहां पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, वहीं कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। वैसे जनतंत्र में सत्ता की होड़ लगी ही रहती है। विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल की सरकार गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं और सत्तारूढ़ दल में सर्वोच्च पद पाने के लिए जोड़-तोड़ लगी रहती है। शायद जनतंत्र का यही रोमांच है। पंजाब, राजस्थान और कर्नाटक में ऐसी क्या बात हो गयी कि वहां के मुख्यमंत्रियों के सर पर खतरे का बादल मंडराने लगा। कुछ बातें जो कैप्टन अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत और बी.एस. येदियुरप्पा के बीच समान हैं वह हैं कि यह तीनों जनता के बीच लोकप्रिय हैं और अपने दम पर मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं उन पर आरोप हैं कि वह तानाशाह प्रकृति के हैं और विधायकों की नहीं सुनते। अमरिंदर सिंह और येदियुरप्पा अब उम्र के उस दराज़ पर पहुंच चुके हैं कि उन्हें स्वेच्छा से किसी को कुर्सी सौंपकर रिटायर हो जाना चाहिए। अमरिंदर सिंह 79 साल के हैं और येदियुरप्पा 78 साल के। येदियुरप्पा पद से इस्तीफा दे चुके हैं लेकिन राजनीति नहीं छोड़ना चाहते हैं। पंजाब और उत्तरप्रदेश में अगले वर्ष की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होना है और कर्नाटक में 2023 के अप्रैल-मई में। ऐसे में इन तीनों रायों को लेकर पार्टी हाईकमान यादा सतर्क दिखाई दे रहे हैं। जहां तक उत्तरप्रदेश की बात की जाए तो फिलहाल वहां का राजनीतिक संकट मिटता दिखाई दे रहा है। क्योंकि बीजेपी हाईकमान ने इशारों में ही सही जता दिया है कि राय में अगला में चुनाव वह योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में लड़ने वाली है। यह अब भले ही बीजेपी की मजबूरी रही हो लेकिन उसने फिलहाल राजनीतिक संकट से अपने को उबार लिया है। रही बात कर्नाटक की तो वहां येदियुरप्पा के बाद कौन सीएम बनता है यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन पार्टी ने संकट को टाल दिया है क्योंकि येदियुरप्पा ने इस्तीफा पर किसी प्रकार की नकारात्मक प्रतियिा नहीं दी है। यह बीजेपी को सुकून जरूर देगी। दूसरी तरफ राजस्थान और पंजाब की बात की जाए तो फिलहाल तो कांग्रेस हाईकमान ने संकट को टाल दिया है लेकिन यह कहना गलत होगा कि आगामी समय में इन रायों में चुनावों के समय किसी प्रकार का राजनीतिक संकट पैदा नहीं होगा। क्योंकि मौजूदा हालातों को देखते हुए लगता है कि चुनावों के समय गुटबाजी जरूर हावी हो सकती है। अब देखना होगा कि आगे कांग्रेस हाईकमान इन रायों के गुटों को कैसे संभाल पाती है।

विजया पाठक

राजनीतिक संग्राम में बदला पेगासस जासूसी विवाद

पेगासस जासूसी कांड

दस देशों के मीडिया संस्थानों के सैकड़ों पत्रकारों ने मिलकर खुलासा किया है कि इजरायली कंपनी एनएसओ के स्पाईवेयर पेगासस के माध्यम से दुनिया भर की सरकारें पत्रकारों, नेताओं, जजों, वकीलों, कारोबारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी करा रही है। फ्रांस की संस्था फॉरबिडन स्टोयरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मिलकर जानकारी जुटाई है कि इजरायली जासूसी नेटवर्क का इस्तेमाल भारत में किया गया। एमनेस्टीस इंटरनेशनल ने पहली कड़ी में बताया है कि भारत में जासूसी का शिकार बने लोगों की संख्यो सैंकड़ों में है। दावा किया गया है कि भारत सरकार ने 2017 से 2019 के दौरान करीब 300 भारतीय मोबाइल नंबरों की जासूसी की है। पेगासस फोन जासूसी विवाद संसद में राजनीति के संग्राम में बदल गया है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं, न्यायाधीशों और पत्रकारों समेत प्रमुख हस्तियों के फोन टैप कराए जाने का आरोप लगाते हुए समूचा विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार पर आक्रामक है। विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में तत्काल चर्चा के साथ संयुक्त संसदीय समिति से जासूसी प्रकरण की जांच कराने की मांग कर रहा है। वहीं सरकार इस पूरे मामले को ही निराधार बता रही है। एनएसओ का कहना है कि वह स्पाइवेयर सरकारों को ही बेचती है। एनएसओ का दावा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए सिर्फ सरकारी एजेंसियों, पुलिस व सेना को ही पेगासस देती है। इसी आधार पर पेगासस प्रोजेक्ट का आंकलन है कि जासूसी सरकारी एजेंसियों ने करवाई। ये कौन सी एजेंसियां है, ये खुलासा नहीं हुआ। संसद में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आरोपों नकारते हुए कहा कि देश में अवैध रूप से फोन की निगरानी नहीं की जा सकती। कांग्रेस ने कहा कि सरकार नागरिकों की जासूसी करवा रही है। हालांकि भारत सरकार ने पेगासस के इस्तेनमाल से मनाही नही की है। इसलिए यह मानना तार्किक है कि सरकारी एजेंसियों ने पेगासस का इस्तेसमाल किया है। वैसे पेगासस या इस जैसे सॉफ्टवेयर पहली बार चर्चा में नहीं हैं। देश के रक्षा संस्थानों की हनीट्रेप के जरिए जासूसी करने के भी अनेक मामले ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स से अंजाम तक पहुंचाए गए हैं। इजरायली प्रौद्योगिकी से वाटसऐप में सेंध लगाकर 1400 भारतीय सामाजिक कार्यकताओं व पत्रकारों की बातचीत के डेटा हैक कर जासूसी का मामला भी 2019 में आम चुनाव के ठीक पहले सामने आया था। इसमें देश के 13 लाख क्रेडिट-डेबिट कार्ड का डेटा लीक कर हैकर्स ऑनलाइन बेच रहे थे। साफ है इन डिजीटल महालुटेरों से निपटना आसान नहीं है।

विजया पाठक

इजरायली जासूसी नेटवर्क की परतें खुलने लगी हैं। 10 देशों के मीडिया संस्थानों के सैकड़ों पत्रकारों ने मिलकर खुलासा किया है कि इजरायली कंपनी एनएसओ के स्पाईवेयर पेगासस के जरिए दुनिया भर की सरकारें पत्रकारों, नेताओं, जजों, वकीलों, कारोबारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी करा रही हैं। फ्रांस की संस्था फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मिलकर जानकारी जुटाई है कि इजरायली जासूसी नेटवर्क का इस्तेमाल भारत में किया गया। किसने किया यह खुलासा बाद में किया जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पहली कड़ी में बताया है कि भारत में जासूसी का शिकार बने लोगों की संख्या 40 से ज्यादा है। वॉशिंगटन पोस्ट और द गार्जियन अखबार के अनुसार अब तक 40 भारतीय पत्रकारों, 3 प्रमुख विपक्षी नेताओं, 2 मंत्रियों और जज की जासूसी की बात पुष्टि हो चुकी है, हालांकि इनमें नाम नहीं बताए हैं। लेकिन, कुछ रिपोर्टस में सामने आ रहा है कि हिन्दुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, नेटवर्क-18, द हिन्दू और इंडियन एक्सप्रेस के प्रमुख पत्रकारों की जासूसी हुई है। जबसे इस कांड की जानकारी आई है, किसका फोन प्रभावित हुआ, यह चर्चा का महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। पेगासस बनाने वाली कंपनी का कहना है कि वह सॉफ्टवेयर सरकारी ग्राहकों को देती है और वह भी केवल जुर्म और

क्या है पेगासस जासूसी मामला

क्यों घिरी केंद्र सरकार, कौन हुआ हैकिंग का शिकार?

इजरायली कंपनी एनएसओ के पेगासस सॉफ्टवेयर से भारत में कथित तौर पर 300 से यादा हस्तियों के फोन हैक किए जाने का मामला अब तूल पकड़ गया है। आइए आपको बताते हैं अब तक इस मामले में क्या-क्या हुआ और यह सॉफ्टवेयर दुनिया का सबसे खतरनाक स्पाईवेयर क्यों माना जाता है।

कहां से आई रिपोर्ट?- लीक हुए आंकड़ों के आधार पर की गई एक वैश्विक मीडिया संघ की जांच के बाद इस बात के और सबूत मिले हैं कि इजराइल स्थित कंपनी एनएसओ ग्रुप के सैन्य दर्जे के मालवेयर का इस्तेमाल पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और राजनीतिक असंतुष्टों की जासूसी करने के लिए किया जा रहा है। पत्रकारिता संबंधी पेरिस स्थित गैर-लाभकारी संस्था फॉरबिडन स्टोरीज एवं मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा हासिल की गई और 16 समाचार संगठनों के साथ साझा की गई। 50,000 से अधिक सेलफोन नंबरों की सूची से पत्रकारों ने 50 देशों में 1,000 से अधिक ऐसे व्यक्तियों की पहचान की है, जिन्हें एनएसओ के ग्राहकों ने संभावित निगरानी के लिए कथित तौर पर चुना। द वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार जिन लोगों को संभावित निगरानी के लिए चुना गया, उनमें 189 पत्रकार, 600 से अधिक नेता एवं सरकारी अधिकारी, 65 व्यावसायिक अधिकारी, 85 मानवाधिकार कार्यकर्ता और कई राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं। इस सूची में मैक्सिको के सर्वाधिक फोन नंबर हैं। इसमें मैक्सिको के 15,000 नंबर हैं।

भारत में किसके फोन हुए हैक?- कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, भाजपा के मंत्रियों अश्विनी वैष्णव और प्रह्लाद सिंह पटेल, पूर्व निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर उन लोगों में शामिल हैं, जिनके फोन नंबरों को हैकिंग के लिए सूचीबद्ध किया गया था। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई पर अप्रैल 2019 में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली उच्चतम न्यायालय की कर्मचारी और उसके रिश्तेदारों से जुड़े 11 फोन नंबर हैकरों के निशाने पर थे। केंद्रीय मंत्रियों वैष्णव और प्रहलाद पटेल के अलावा जिन लोगों के फोन नंबरों को निशाना बनाने के लिये सूचीबद्ध किया गया उनमें चुनाव पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के संस्थापक जगदीप छोकर और शीर्ष वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार सूची में राजस्थान की मुख्यमंत्री रहते वसुंधरा राजे सिंधिया के निजी सचिव और संजय काचरू का नाम शामिल था, जो 2014 से 2019 के दौरान केन्द्रीय मंत्री के रूप में स्मृति ईरानी के पहले कार्यकाल के दौरान उनके विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) थे। इस सूची में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े अन्य जूनियर नेताओं और विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया का फोन नंबर भी शामिल था।

जांच का आधार- यह जांच एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडेन स्टोरीज को प्राप्त लगभग 50 हजार नामों और नंबरों पर आधारित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इनमें से 67 फोन की फॉरेन्सिक जांच की। इस दौरान 23 फोन हैक मिले, जबकि 14 अन्य में सेंधमारी की कोशिश की पुष्टि हुई। द वायर ने खुलासा किया कि भारत में भी दस फोन की फॉरेन्सिक जांच करवाई गई। ये सभी या तो हैक हुए थे या फिर इनकी हैकिंग का प्रयास किया गया था।

आतंक के खिलाफ इस्तेमाल के लिए। लेकिन भारत में पक्ष-विपक्ष, सरकारी अधिकारी, मीडिया, मानव अधिकार पर काम करने वाले लागों के नाम शामिल हैं। वास्तव में जब कंपनी माल बेच देती है, उसके बाद उसका इस पर अख्तियार नहीं कि

ग्राहक उसे किस तरह इस्तेमाल करता है। कई लोगों का कहना है किसी का फोन इस तरह से हैक करने में दिक्कत क्या है? जरूर उनके पास कुछ छिपाने लायक बात होगी, वरना उन्हें ऐतराज क्यों होता? यह कुतर्क है। क्या आप अपने ई-मेल का पासवर्ड सबको बताते हैं? यदि नही, तो क्या आप कुछ छिपाने लायक काम करते हैं? जिंदगी के हर दायरे में हम तय करते हैं कि किसके साथ, क्या साझा करेंगे। यह बदलता भी रहता है। आज आपने काम के बारे में किसी सहकर्मी से शेयर करते हैं, कल उसका पद बदलने पर शायद न करना चाहें। मूल बात यह है कि किसे क्या बताना है, इस पर नियंत्रण आपके हाथों में है। इय नियंत्रण के अपने हाथों से निकल जाने पर हम बेबस, लाचार हो जाते हैं और आपकी बातें, आपके फोटो, किस दिन, से कितनी बात की, यह सब आपकी अनुमति के बगैर, आपकी जानकारी के बगैर, किसी सरकार की एजेंसी के लोगों तक पहुंच जाती है। एक तरह से आप खुद को नग्न महसूस करते हैं, जिससे आपकी गरिमा का भी सवाल उठता है। सार्वजनिक जिंदगी बिताने वाले, चाहे नेता हो या पत्रकार, जज या चुनाव आयोग के कमिश्नर, सभी लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। लेकिन जवाबदेही के लिए पारदर्शिता चाहिए। हैकिंग निगरानी का यंत्र है, पारदर्शिता नहीं। जब उनका फोन हैक होता है, तो उनकी

निजी जिंदगी की जानकारी का, उन्हें काबू में रखने में इस्तेमाल हो सकता है।

पेगासस कांड की वजह से यह चर्चा हो रही है। लेकिन इसके अलावा निगरानी के कई यंत्र है। गूगल, वॉट्सएप, फ़ेसबुक, यह सब गुप्त तरीके से हमारी जानकारी प्राप्त करते हैं, इससे मुनाफ़ा कमाते हैं (आपकी पंसद-नापसंद के आधार पर विज्ञापन दिखाकर) और कभी-कभी उआपकी जानकारी सरकार के साथ साझा करते हैं। सबसे भयावह बात यह है कि निजी कंपनियों का मुनाफ़ा नागरिकता और लोकतंत्र को कमजोर करने से कमाया जा रहा है। दुनिया भर की सरकारों द्वारा अपने नागरिकों की जासूसी करवाने का खुलासा करने वाले 16 मीडिया संस्थानों को साझा पेगासस प्रोजेक्ट के तहत एक और बड़ा खुलासा किया गया। इस स्पाइवेयर के निशाने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उनके 5 करीबी मित्र, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, पं. बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और पूर्व सीजेआई पर यौन उत्पीड़न वाली महिला भी थी। यही नहीं केन्द्रीय सूचना, प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और उनकी पत्नी का भी नाम इस सूची में है। केन्द्रीय राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल और उनसे जुड़े 18 लोगों के मोबाइल नंबर भी सूची में है। केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के ओएसडी रहे संजय काचरू,

पेगासस स्पाईवेयर मामला भारत के लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक क्यों?

आप एक निजी संस्था को किसी के सिस्टम में हैक करने के लिए नहीं कह सकते। पेगासस मामले में यही हुआ लगता है। मौजूदा क़ानून के तहत सरकार किसी तीसरे पक्ष को किसी के सिस्टम को हैक करने के लिए नहीं कह सकती। सरकार को घर की तलाशी लेने का वारंट मिल सकता है अगर उन्हें लगता है कि वहां कुछ सबूत हैं या कोई अपराध किया है। वे अदालत से वारंट प्राप्त कर सकते हैं और कह सकते हैं कि उनके पास यह मानने की वजह है कि घर में अपराध के कुछ सबूत हैं। वारंट के साथ वे घर में घुसकर तलाशी ले सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं कर सकते कि किसी चोर को शामिल करें और कहें कि जाओ और इस घर से सबूत लेकर आओ। चूंकि सरकार ऐसा कर रही है इस बात को कानूनी नहीं बना देता। अगर सरकार निगरानी करना चाहती है तो भी उसके लिए एक वैध प्रक्रिया है। सरकार कानून को दरकिनार कर किसी और से यह काम नहीं करवा सकती। इस तरह की गतिविधि से जिन्हें निशाना बनाया गया है उनके निजता के मौलिक अधिकार का पूरा हनन हुआ है और सरकार का सिर्फ़ यह कह देना यह रिपोर्ट झूठी है काफ़ी नहीं है। सरकार के किसी बयान से यह साफ़ नहीं होता कि उसने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा या नहीं ख़रीदा या इस्तेमाल किया या नहीं किया। सरकार का बस इतना कहना है कि हमने कोई अवैध इंटरसेप्शन नहीं की। अगर इसका मतलब ये है कि सरकार कह रही है कि जो भी उसने किया वो वैध था तो उसका खुलासा उसे करना चाहिए। वो जानकारी फ़िलहाल सामने नहीं आ रही है तो कहीं न कहीं लोगों के दिलों में एक दहशत फ़ैल रही है। लोगों को लग रहा है कि अगर इतने महत्वपूर्ण लोगों के डेटा का आप सर्विलांस कर रहे हैं तो आम आदमी किस खेत की मूली है। इस कानूनी ढांचे का उपयोग करके डेटा को वैध रूप से इंटरसेप्ट करना संभव है। लेकिन कानूनी ढांचे के साथ समस्याएं हैं। सरकार दोनों मुद्दों को भ्रमित करने की पूरी कोशिश कर रही है। या तो आप कहें कि हमने क़ानून के मुताबिक ऐसा किया। उस मामले में उन्हें उन आदेशों को प्रस्तुत करना चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि आधार क्या था और किस प्रयिा का पालन किया गया था। अगर सरकार यह कहने की कोशिश कर रही है कि इस तरह की चीज़ें वास्तव में सर्विलांस या निगरानी है तो ऐसा नहीं है। यह सीधे तौर पर हैकिंग है। यह पूरी तरह से अवैध है। इसका कोई क़ानूनी आधार नहीं है। अगर सरकार कहती है कि उसका इससे कोई लेना–देना नहीं है तो उसे पेगासस बनाने वाली कंपनी एनएसओ के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करनी चाहिए और यह कहना चाहिए कि एनएसओ एक शत्रुतापूर्ण विदेशी संस्था है और यह भारतीय नागरिकों के फोन हैक कर रही है। सरकार ऐसा करने को तैयार नहीं है। सवाल यह है कि सरकार वास्तव में क्या कहना चाह रही है। लगभग हर व्यक्ति को आज डर है कि उसके निजता के अधिकार का सम्पूर्ण हनन हो रहा है या हो सकता है।

राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के निजी सचिव प्रदीप अवस्थी और विहिप के पूर्व नेता प्रवीण तोगड़िया के नंबर भी पेगासस बनाने वाली इजराइली कंपनी एनएसओ के डेटाबेस में हैं। सिर्फ प्रशांत किशोर ने ही फोरेंसिक विश्लेषण के लिए फोन एमनेस्टी

खतरनाक होता है वायरस

पेगासस स्पाईवेयर इजराइल की सर्विलांस फर्म एनएसओ ने तैयार किया है। पेगासस नाम का यह एक प्रकार का वायरस इतना खतरनाक व शाक्तिशाली है कि लक्षित व्यक्ति के मोबाइल में मिस्ड कॉल के जरिए प्रवेश कर जाता है। इसके बाद यह मोबाइल में मौजूद सभी डिवाइसों को एक तो सीज कर सकता है, दूसरे जिन हाथों के नियंत्रण में यह वायरस है, उनके मोबाइल सैन पर लक्षित व्यक्ति की सभी जानकरियां क्रमवार हस्तांरित होने लगती हैं। लक्षित व्यक्ति की कोई भी जानकारी सुरक्षित व गोपनीय नहीं रह जाती। यह वायरस इतना चालाक है कि निशाना बनाने वाले मोबाइल पर हमले के कोई निशान नहीं छोड़ता। यह महज एक सेल्फ-डिस्ट्रक्ट ऑप्शन (विनाशकारी विकल्प) के रूप में आता है, जिसे किसी भी समय इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी खासियत है कि इसके प्रोग्राम को किसी स्मार्टफोन में डाल दिया जाए तो यह हैकर का काम करने लगता है। नतीजतन फोन में संग्रहित सामग्री आडियो, वीडियो, चित्र, लिखित सामग्री, ईमेल और व्यक्ति के लोकेशन तक की जानकारी पेगासस हासिल कर लेता है। इसकी विलक्षणता यह भी है कि यह एन्प्टेड संदेशों को भी पढ़ने लायक स्थिति में ला देता है। इसके बाद यह मोबाइल में मौजूद सभी डिवाइसों को एक तो सीज कर सकता है, दूसरे जिन हाथों के नियंत्रण में यह वायरस है, उनके मोबाइल सैन पर लक्षित व्यक्ति की सभी जानकारियां मवार हस्तांरित होने लगती हैं। इजरायल की एक निजी कंपनी, एनएसओ, ने पेगासस नाम हैकिंग सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसे सवह केवल अन्य देश की सरकारों को बेचती है। यह सॉफ्टवेयर आपके जाने बिना, आपके फोन से 24 घंटे जानकारी भेजता रहा है। फोन से कॉन्टैक्ट, फोटो, मैसेज इत्यादि सरकारी एजेंसी से साझा होते रहते हैं, जब तक वह फोन आप इस्तेमाल करेंगे। यह सॉफ्टवेयर फोन के हार्डवेयर को प्रभावित करता है, न कि फोन में डाले गए ऐप को। ज्यादातर हैकिंग के मामलों में जिस व्यक्ति का फोन टारगेट होता है, वह भूल से ही सही, किसी के द्वारा भेजी गई लिंक या मैसेज पर क्लिक कर देता है। पेगासस फोन को बिना इस सबके भी संक्रमित कर सकता है।

पेगासस जासूसी कांड की सच्चाई बताए मोदी सरकार

इंटरनेशनल को दिया जिसमें हैकिंग की पुष्टि हुई। एनएसओ का कहना है कि वह स्पाइवेयर सरकारों को ही बेचती है। इसी आधार पर पेगासस प्रोजेक्ट का आंकलन है कि जासूसी सरकारी एजेंसियों ने करवाई। ये कौन सी एजेंसियां है, ये खुलासा नहीं हुआ। संसद में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि देश में अवैध रूप से फोन की निगरानी नहीं की जा सकती। कांग्रेस ने कहा कि सरकार नागरिकों की जासूसी करवा रही है। भाजपा ने कहा कि सूची में नंबर होने से यह साबित नहीं होता कि जासूसी की गई।

एनएसओ का दावा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए सिर्फ सरकारी एजेंसियों, पुलिस व सेना को ही पेगासस देती है। भारत सरकार ने पेगासस के इस्तेमाल से मनाही नही की है। इसलिए यह मानना

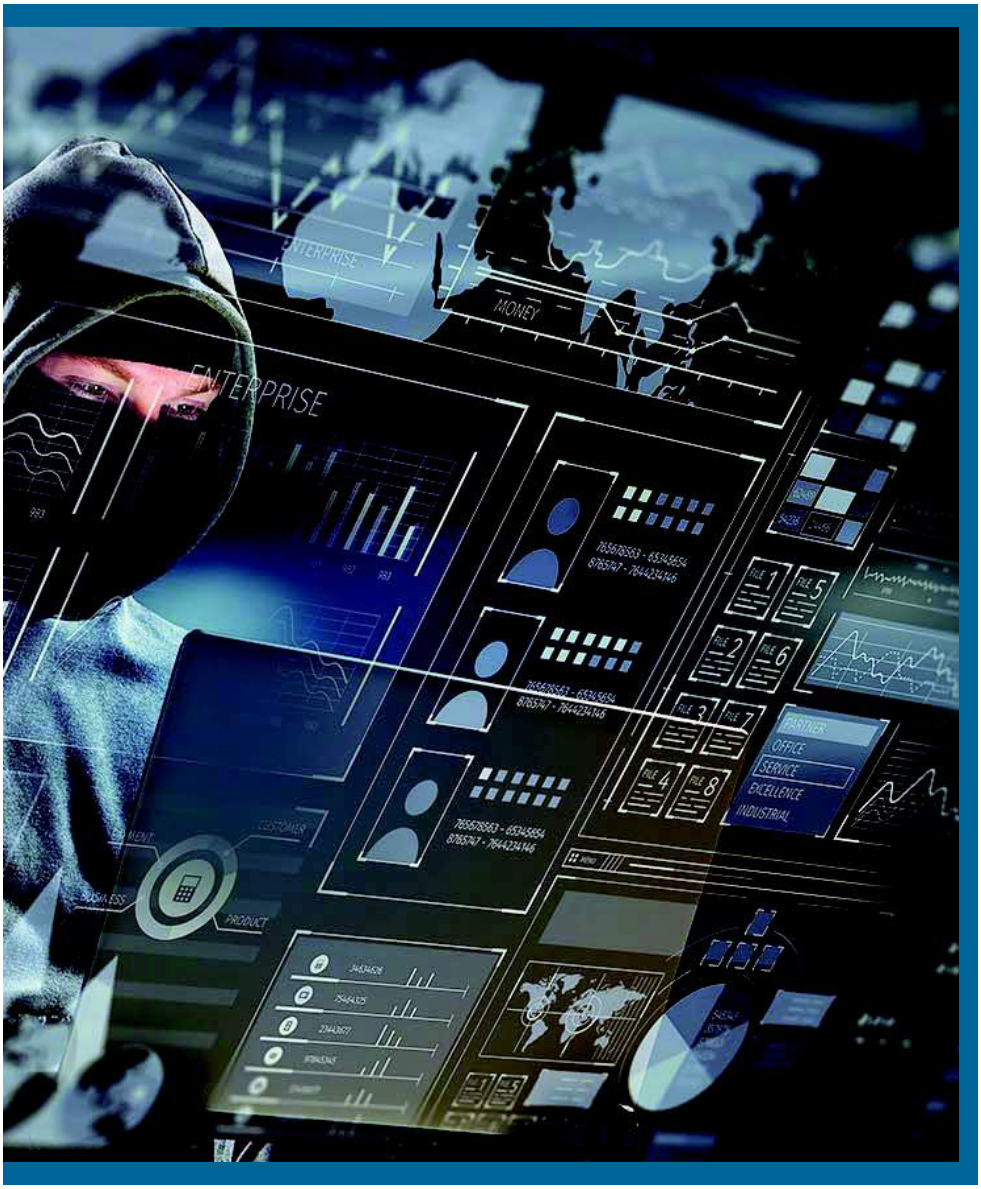

तार्किक है कि सरकारी एजेंसियों ने पेगासस इस्तेमाल किया। तीन दशक पहले विपक्षी नेता राजीव गांधी के घर पर पुलिस के दो जवानों की निगरानी के मुद्दे पर चंद्रशेखर सरकार गिर गई। उसके पहले 1988 में टेलीफोन टेपिंग के मामले पर कर्नाटक में हेगड़े की सरकार गिरी। पुराने किस्सों के अंजाम देखते हुए पेगासस की सरकारी खरीद या वैध इस्तेमाल के तीखे सवाल पर मंत्रियों और प्रवक्ताओं ने होंठ सी रखे हैं।

सन 1885 के जिस कानून के दम पर टेलीफोन टेपिंग के सरकारी हक की बात हो रही है, वह गुजरे जमाने की बात है। मोबाइल में सेंध लगाने का अधिकार हासिल करने के लिए गृह मंत्रालय ने 20 दिसंबर 2018 को ओदश पारित किया था। इसके तहत भारत सरकार की 9 खुफिया एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को इंटरनेट व मोबाइल में जासूसी

पेगासस को कौन खरीद सकता है?

एनएसओ ग्रुप केवल अधिकृत सरकार के साथ काम करने का दावा करती है। पेगासस को सार्वजनिक रूप से मेक्सिको और पनामा की सरकार द्वारा उपयोग के लिए जाना जाता है। 40 देशों में इसके 60 ग्राहक हैं। कंपनी ने कहा कि उसके 51 प्रतिशत उपयोगकर्ता इंटेलिजेंस एजेंसियों, 38 प्रतिशत कानून प्रवर्तन एजेंसियों और 11 प्रतिशत सेना से संबंधित हैं। वैसे पेगासस स्पाईवेयर साफ्टवेयर की कीमत क्या होगा ये एनएसओ ग्रुप और खरीदने वाले के बीच तय होती है जोकि करोड़ों रुपये प्रति एक यूजर के हिसाब से चार्ज की जाती है। पेगासस स्पाइवेयर लाइसेंस के साथ बेचा जाता है। इसकी कीमत क्या होगी ये कंपनी और खरीदने वाले के बीच होने वाली डील पर तय होता है। इसके एक लाइसेंस की कीमत 70 लाख रुपए तक हो सकती है। एक लाइसेंस से कई स्मार्टफोन को ट्रैक किया जा सकता है। 2016 के अनुमानों के अनुसार, पेगासस का उपयोग करने वाले केवल 10 लोगों की जासूसी करने के लिए, एनएसओ ग्रुप ने करीब 9 करोड़ रुपए की फीस ली थी। 2016 की प्राइस लिस्ट के अनुसार, एनएसओ ग्रुप ने 10 डिवाइस को हैक करने के लिए अपने ग्राहक से 650,000 डॉलर (करीब 4.84 करोड़ रुपए) की फीस ली थी। इसके अलावा, इंस्टॉलेशन के लिए 500,000 डॉलर (करीब 3.75 करोड़ रुपए) अलग से लिए थे।

पेगासस मामले में एमनेस्टी ने किया भाजपा का दावा खारिज

पेगासस जासूसी कांड को फर्जी करार देने वाली बीजेपी के दावे की पोल खुल गई है। खुद एमनेस्टी इंटरनेशल ने पेगासस जासूसी कांड के संबंध में उपलब्ध कराए गए अपने डेटा को 100 फीसदी सही करार दिया है। एमनेस्टी के इस स्पष्टीकरण के बाद एक बार फिर बीजेपी

जानकारी मांगी थी। पेगासस के खिलाफ विदेश में चल रही कानूनी लड़ाई में वॉट्सएप के साथ फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल है। लेकिन डिजिटल के सबसे बड़े बाजार भारत की सरकार, संसद और सुप्रीम कोर्ट, पेगासस के मुद्दे पर ट्राजन हॉर्स सिंड्रोम का शिकार दिखते हैं। मोबाइल फ़ोन की जासूसी, लोगों के जीवन के अधिकार से खेलने सरीखा है। सरकार, संसद और सुप्रीम कोर्ट समेत अधिकांश संस्थाएं पेगासस मामले में अपनी संवैधानिक भूमिका के निर्वहन में विफल रहे। लेकिन

सियासत में जासूसी कितनी उचित, कितनी अनुचित?

देश की एकता और अखंडता के इस मामले में ठोस कार्यवाही जरूरी है। सन 2019 में जब कैलिफोर्निया की कोर्ट में फेसबुक ने रहस्य खोला कि कई देशों में पेगासस स्पाईवेयर का प्रयोग कर उसके क्लाइंट्स के फोन की सभी जानकारियां ली जा रही है, जिसमें भारत भी था। तब सॉफ्टवेयर बनाने वाली इजरायली कंपनी एनएसओ ने इसे कुबूल किया, लेकिन कहा कि केवल संप्रभु देशों के खुफिया प्रतिष्ठानों को ही पेगासस देती है। भारत सरकार ने संसद में हंगामे के बीच जासूसी के आरोप से इंकार नहीं किया।

की किरकिरी शुरु हो गई है। जिस वजह से केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई है। एमनेस्टी ने अपने स्पष्टीकरण में स्पष्ट तौर पर इस बात का उल्लेख किया है कि वह पेगासस को लेकर किए जा रहे दावों के साथ मज़बूती के साथ खड़ा है। एमनेस्टी ने कहा है कि सोशल मीडिया और विभिन्न मीडिया संस्थान के रिपोर्ट्स को वह पूरी तरह से खारिज करता है। एमनेस्टा ने कहा है कि यह भ्रामक दावे सिर्फ ध्यान भटकाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एक इज़राइली मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया था कि खुद एमनेस्टी ने कथित तौर पेगासस स्पाइवेयर के ज़रिए जासूसी की बात से अपना पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन जल्द ही एमनेस्टी ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वैसे भी पूरी दुनिया में द क्रिमिनल लॉ का एक ही सिद्धांत है कि अपराध करने के बावजूद अभियुक्त को यही समझाया जाता है कि वो इंसाफ की देवी के आगे कभी भी यह न क़बूल करे कि उसने कोई गुनाह किया है। यही सिद्धांत दुनिया की सरकारों पर भी लागू होता है। इसलिये क़ानून के जानकारों की निगाह में कुछ दिनों के शोरशराबे के बाद केंद्र सरकार भी इससे अपना पल्ला झाड़कर बच निकलेगी। पर देश की जनता को इस सवाल का जवाब नहीं मिल पायेगा कि पत्रकारों, नेताओं, जजों समेत इतने सारे लोगों की जासूसी फिर कौन करवा रहा था? लेकिन इतना फर्क जरुर पड़ेगा कि इस खुलासे के बाद सरकार पर सवालिया निशान लग जायेगा और विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लोगों में यह डर बैठ जायेगा कि कहीं उनकी भी ख़ुफ़िया निगरानी तो नहीं हो रही है।

क्या निजता पर प्रहार नहीं है जासूसी?

कैलिफोर्निया की कोर्ट ने 16 जुलाई 2020 के अपने फैसले में फेसबुक द्वारा लगाए आरोप सही पाए। दुनिया भर की लोकतांत्रिक सरकारों के लिए यह एक बड़ा धब्बा था। पश्चिमी दुनिया के अखबारों ने खुलासा किया कि भारत सरकार अपने कुछ मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट जजो, विपक्ष के नेताओं और दर्जनों पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के फोन इस स्पाईवेयर के जरिए टेप कर रही है। विपक्ष का आरोप है सरकार मामले को भी विदेशी साजिश करार देकर कमजोर साबित करने की फिराक में है। इंटरनेशनल मीडिया कंसोर्टियम के खुलासे और आरोप गंभीर हैं और अगर आगे चलकर इन पर मुहर लग जाती है, तो सरकार पर कई सवाल खड़े होना लाजिमी है। अगर विदेशी मीडिया के खुलासे और आरोपों को सच माने तो सवाल उठता है- सुप्रीम कोर्ट के जज और सरकार के मंत्रियों की जासूसी की नौबत क्यों आई? अगर केन्द्रीय मंत्री संदिग्ध हैं तो देश सुरक्षित कैसे रहेगा। क्या बड़े-बड़े फैसले देने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज भी ऐसे शक के दायरे में लाए जा सकते हैं? विपक्ष को शक है कि सरकार की खुफिया एजेंसियों द्वारा इस तरह के सर्विलांस कहीं बड़े पर्दे पर बैठे लोगों को डराने और अपने अनुकूल व्यवहार करवाने के लिए तो नहीं किया गया है? संसद से लेकर सड़क तक बेचैनी है। उम्मीद है, सच जल्द ही सामने आएगा।

दावा किया गया है कि भारत सरकार ने 2017 से 2019 के दौरान करीब 300 भारतीय मोबाइल नंबरों की जासूसी की है। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार ने पेगासस स्पायवेयर की मदद से पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, विपक्ष के नेता और बिजनेसमैन के फोन हैक किए थे। पेगासस फोन जासूसी विवाद संसद में राजनीति के संग्राम में बदल गया है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं, न्यायाधीशों और पत्रकारों समेत प्रमुख हस्तियों के फोन टैप कराए जाने का आरोप लगाते हुए समूचा विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार पर आक्रामक है। विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में तत्काल चर्चा के साथ संयुक्त संसदीय समिति से जासूसी प्रकरण की जांच कराने की मांग कर रहा है। वहीं सरकार इस पूरे मामले को ही निराधार बता रही है। रायसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सवाल किया कि सरकार सिर्फ इतना स्पष्ट करे कि सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर की निर्माता कंपनी एनएसओ से कोई सौदा किया है अथवा नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में पूर्व सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में आतंकवाद या सुरक्षा के मसले पर यदि जांच

पेगासस जासूसी कांड का पक्ष-विपक्ष की प्रतिक्रियाएं

पेगासस एक हथियार है। इजरायली सरकार इसे हथियार मानती है। ये हथियार आतंकवादियों और अपराधियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने इस हथियार को हिंदुस्तान की संस्थाओं और लोकतंत्र के खिलाफ प्रयोग किया है। यह सिर्फ मेरी निजता का मामला नहीं है, जनता की आवाज पर आक्रमण है। गृहमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और नरेंद्र मोदी पर न्यायिक जांच होनी चाहिए क्योंकि इसका ऑथराइजेशन पीएम और गृहमंत्री ही कर सकते हैं।

राहुल गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष

लोकतंत्र में विरोधी दल के नेताओं की जासूसी करने, ख़ुद के मंत्रियों की भी जासूसी करने के सबूत मिले हैं। हमारे राहुल गांधी की भी जासूसी की गई है। इसकी जांच होने के पहले ख़ुद अमित शाह साहब को रिज़ाइन करना चाहिए। मोदी साहब की इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर लोकतंत्र के उसूलों से चलना चाहते हैं तो आप इस जगह पर होने के काबिल नहीं हैं।

मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता कांग्रेस

इस तरह की जासूसी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। मोदी सरकार ने ऐसी सुरक्षा नीति बना दी है जिससे विरोधियों की आवाज दवा दी जाए। उनकी आवाज को घोंट सकें, लोकतंत्र को खत्म कर सकें। मोदी सरकार कानून और संविधान की हत्या कर रही है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है।

कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री, मप्र

एजेंसियां किसी की निगरानी करती है तो इसके लिए पूरी प्रयिा अपनाई जाती है। भारत की स्थिर सरकार को अस्थिर करने के हथकंडे पश्चिमी मीडिया अपनाता रहा है। इसलिए उसने कथित पेगासस प्रोजेक्ट बम ऐसे समय पटका, जब संसद के मानसून सत्र की शुरूआत होनी थी। नतीजतन पिछले सात वर्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से विपक्ष को हंगामे का नया हथियार मिल गया। डिजिटल सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए दुनिया की सरकारें अपने नागरिकों, विरोधियों या अन्य संदिग्धों की जासूसी करवाती रही हैं। यह नया कथित खुलासा 16 मीडिया संस्थानों ने मिलकर किया है। यदि वास्तव में इन हस्तियों के मोबाइल फोन टेप किए जा रहे थे तो इसकी

पेगासस जासूसी कांड का पक्ष-विपक्ष की प्रतिक्रियाएं

क्रोनोलॉजी समझिए। ये खुलासे मानसून सत्र से ठीक पहले ही क्यों किए जा रहे हैं? देश को बदनाम कर रहे हैं। विघटनकारी और अवरोधक शक्तियां अपने षड्यंत्रों से भारत की विकास यात्रा को नहीं रोक पायेंगी। इस तरह के आचरण से देश की ही बदनाम होती है।

अमित शाह, गृहमंत्री

देश में आतंकवाद या सुरक्षा के मसले पर यदि जांच एजेंसियां किसी की निगरानी करती है तो इसके लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारत की स्थिर सरकार को अस्थिर करने के हथकंडे पश्चिमी मीडिया अपनाता रहा है। इसलिए उसने कथित पेगासस प्रोजेक्ट बम ऐसे समय पटका, जब संसद के मानसून सत्र की शुरूआत होनी थी।

रविशंकर प्रसाद, पूर्व सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री

सरकार सिर्फ इतना स्पष्ट करे कि सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर की निर्माता कंपनी एनएसओ से कोई सौदा किया है अथवा नहीं? यदि किया है तो यह देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद

सच्चाई जानने के लिए इन लोगों को अपने फोन फॉरेंसिक जांच के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल को देने होंगे। अब तक अकेले प्रशांत किशोर ने अपना मोबाइल जांच के लिए सौंपा है। यहां सवाल उठता है कि यदि अन्य लोग मोबाइल पर आपत्तिजनक कोई बात नहीं कर रहे थे, तब वे अपने फोन जांच के लिए क्यों नहीं दे रहे? इस खुलासे से संसद से सड़क तक बेचैनी जरूर है, लेकिन इसके परिणाम किसी अंजाम तक पहुंचने वाले नहीं हैं? यह मुखबिरी पेगासस के माध्यम से भारत के लोगों पर ही नहीं 40 देशों के 50 हजार लोगों पर कराई जा रही थी। इस सॉफ्टवेयर की निर्माता कंपनी एनएसओ ने दावा किया है कि इसे वह अपराध और आतंकवाद से लड़ने के लिए

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पेगासस जासूसी कांड

पेगासस जासूसी कांड का पक्ष-विपक्ष की प्रतिक्रियाएं

पेगासस जासूसी कांड देश की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा करने वाली घटना है। अगर महाराष्ट के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का फोन भी टैप हो रहा हो तो हैरानी की बात नहीं। क्योंकि यह एक ऐसी घटना है जिसमें किसी के भी फोन टेपिंग हो सकते हैं।

संजय राउत, प्रवक्ता, शिवसेना

केंद्र सरकार ने इजरायली स्पाईवेयर पेगासस द्वारा राजनेताओं और पत्रकारों की कथित जासूसी की है। सरकार प्रशांत किशोर के साथ हमारी मुलाकातों की जासूसी कर रही थी। हमारी बैठकों को निगरानी में रखा। प्रशांत किशोर ने अपने फोन का ऑडिट किया और पता चला कि पेगासस स्पाइवेयर के माध्यम से हमारी एक बैठक सरकार को पता थी। जासूसी रोकने के लिए उसने अपना फोन प्लास्टर कर दिया है।

ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री, प.बंगाल

विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, केंद्रीय मंत्रियों समेत कई को भी पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल करने वाली अज्ञात कंपनी ने अपना निशाना बनाया था। मैंने पांच बार मोबाइल हैंडसेट बदला, लेकिन हैकिंग जारी है। त्रिपुरा में होटल से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई। यह ऐसी घटनाएं है जो दर्शाती है कि जासूसी हो रही है।

प्रशांत किशोर, चुनावी रणनीतिकार

ममता बैनर्जी ने अपने फोन में क्या लगवाया?

केवल सरकारों को ही बेचती है। पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद में एनएसओ का पत्र लहराते हुए पूरे मामले को नकार दिया। तय है कि सरकार ने ऐसा कोई अनाधिकृत काम नहीं किया है, जो निंदनीय हो अथवा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता हो। इसीलिए इस रहस्य का खुलासा करने वाली फ्रांस की कंपनी फारबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ऐसे कोई तथ्य नहीं दिए हैं, जो फोन पर की बातचीत को प्रमाणित करते हों? बिना साक्ष्यों के कथित खुलासा व्यर्थ है और हंगामा भी संसद में कीमती समय की बर्बादी है।

वैसे पेगासस या इस जैसे सॉफ्टवेयर

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पेगासस जासूसी कांड

पेगासस जासूसी कांड का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर अनुरोध किया गया है कि पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, नेताओं और अन्य की इजराइली स्पाइवेयर पेगासस का इस्तेमाल करके सरकारी एजेंसियों द्वारा कथित रूप से जासूसी कराए जाने की खबरों की न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा जांच कराई जाए। दायर याचिका में कहा गया है कि पेगासस कांड गहरी चिंता का विषय है और यह भारतीय लोकतंत्र, न्यायपालिका और देश की सुरक्षा पर गंभीर हमला है तथा व्यापक स्तर और बिना किसी जवाबदेही के निगरानी करना नैतिक रूप से गलत है। याचिका में कहा गया है, निजता कुछ छुपाने की इच्छा नहीं होती। यह स्वयं की ऐसी जगह होती है, जहां हमारे विचार एवं हमारा अस्तित्व किसी ओर के उद्देश्यों के साधन नहीं होते हैं। यह गरिमा के लिए आवश्यक तत्व है। इसमें कहा गया है कि पेगासस का उपयोग केवल बातचीत सुनने के लिए नहीं होता, बल्कि इसके उपयोग से व्यक्ति के जीवन के बारे में पूरी डिजिटल जानकारी हासिल कर ली जाती है और इससे ना केवल फोन का मालिक असहाय हो जाता है बल्कि उसकी संपर्क सूची में शामिल हर व्यक्ति ऐसा महसूस करता है। जनहित याचिका में दावा किया गया है कि ऐसा बताया जा रहा है कि एनएसओ ग्रुप कंपनी के ग्राहकों ने 2016 के बाद से करीब 50,000 फोन नंबर को निशाना बनाया है।

पहली बार चर्चा में नहीं हैं। देश के रक्षा संस्थानों की हनीट्रेप के जरिए जासूसी करने के भी अनेक मामले ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स से अंजाम तक पहुंचाए गए हैं। इजरायली प्रौद्योगिकी से वाट्सऐप में सेंध लगाकर 1400 भारतीय सामाजिक कार्यकताओं व पत्रकारों की बातचीत के डेटा हैक कर जासूसी का मामला भी 2019 में आम चुनाव के ठीक पहले सामने आया था। इसमें

देश के रक्षा संस्थानों की हनीट्रेप के जरिए जासूसी करने के भी अनेक मामले ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स से अंजाम तक पहुंचाए गए हैं।

देश के 13 लाख डिट-डेबिट कार्ड का डेटा लीक कर हैकर्स ऑनलाइन बेच रहे थे। साफ है इन डिजीटल महा लुटेरों से निपटना आसान नहीं है। दुनिया भर में ड़ेढ़ करोड़ उपभोक्ताओं वाले वाट्सऐप में सेंघ लगाकर पत्रकारों विपक्षी नेताओं, मानवाधिकारों व सामाजिक कार्यकताओं की जासूसी करने के आरोप भी लगे थे, लेकिन इसमें भी कोई प्रमाण अब तक सामने नहीं आए हैं। उस

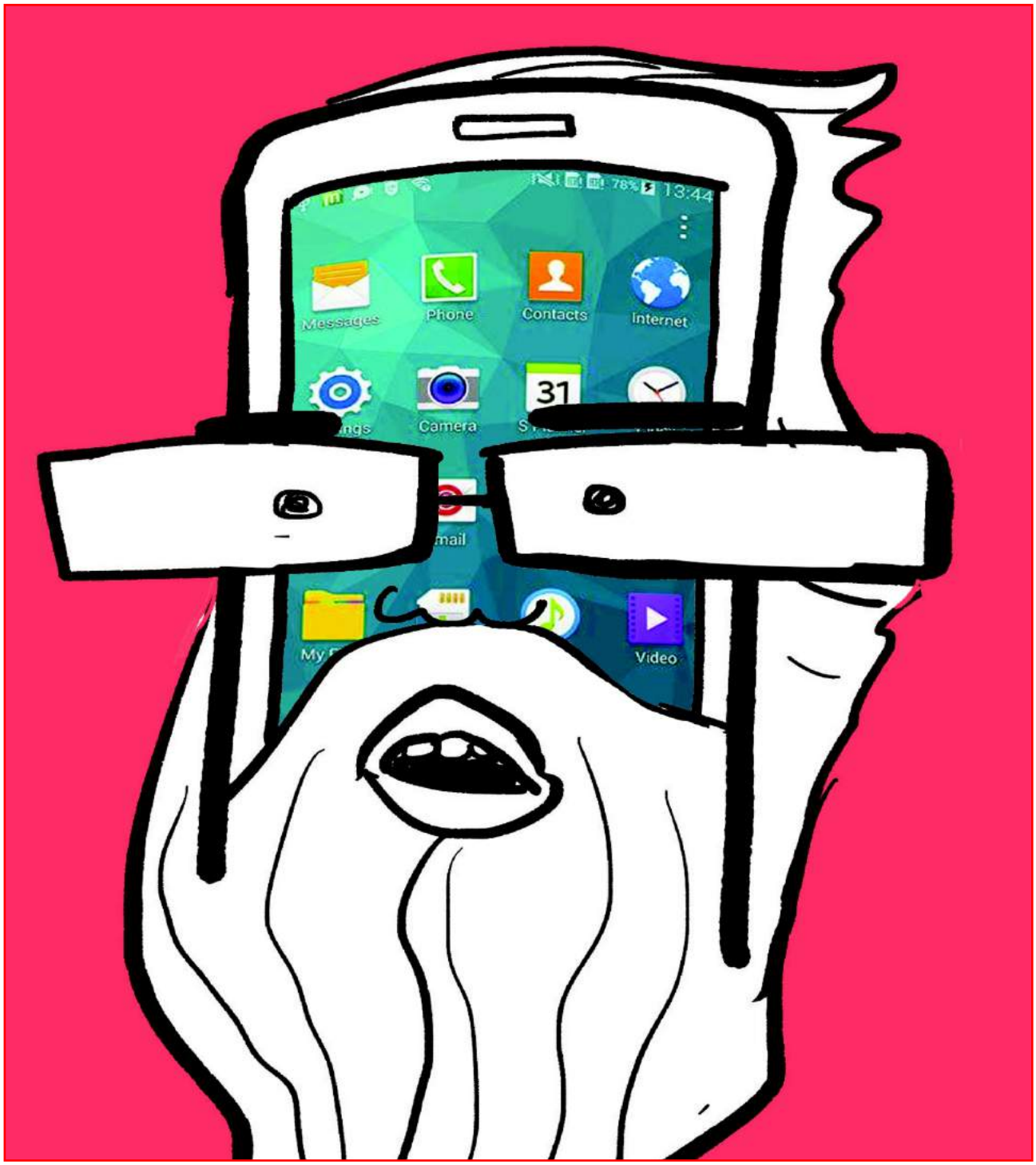

समय फेसबुक के स्वामित्व वाली वाट्सऐप ने स्वयं जानकारी दी थी कि इजरायली स्पाइवेयर पेगासस के मार्फत चार महाद्वीपों में करीब 1400 लोगों के फोनों में सेंघ लगाई गई है। इस रहस्योद्घाटन के बाद वाट्सऐप ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में

स्थित संघीय न्यायालय में एनएसओ समूह के विरुद्ध मुकदमा भी दायर किया हुआ है। इस एफआईआर में वाट्सऐप ने कहा है कि 1400 फोन में स्पाइवेयर पेगासस डालकर उपभोक्ताओं की महत्वपूर्ण जानकारी चुराई गई हैं। हालांकि वाट्सऐप ने कुटिलता बरतते हुए प्रभावितों की संख्या सही नहीं बताई है। यह जानकारी तब चुराई गई थी,

इस स्पाइवेयर के जरिए विपक्षी नेताओं और केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्षरत लोगों की अपराधियों की तरह जासूसी कराई गई।

जब भारत में अप्रैल-मई 2019 में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में विपक्ष ने यह आशंका जताई थी कि इस स्पाइवेयर के जरिए विपक्षी नेताओं और केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्षरत लोगों की अपराधियों की तरह जासूसी कराई गई। हालांकि इस मामले में भी अब तक कोई तथ्यपूर्ण सच्चाई सामने नहीं आई है। वैसे

कब से चल रहा था पूरा मामला?

जिन लोगों के फ़ोन में पेगासस की पुष्टि हुई है उनमें से एक हैं चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर है। बीते 14 जुलाई को प्रशांत किशोर के फ़ोन की फ़ॉरेंसिक जांच की गई और पाया गया कि जिस दिन उनके फ़ोन की जांच की गई उस दिन भी फ़ोन को पेगासस से हैक किया गया था। प्रशांत किशोर साल 2014 के चुनाव में बीजेपी के साथ काम कर चुके हैं, इस साल हुए पश्चिम बंगाल चुनाव में वह टीएमसी के रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की लैब ने पाया कि अप्रैल में जब वह बंगाल चुनाव के काम में लगे थे उस दौरान भी प्रशांत किशोर के फ़ोन को हैक किया गया था। हाल ही में उन्होंने एनसीपी नेता शरद पवार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। ये पड़ताल दावा करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2017 के इजराइल दौरे के साथ ही एनएसओ के सिस्टम में भारतीय नंबरों की एंट्री शुरू हुई। इस लिस्ट में सिर्फ़ राजनेताओं, नौकरशाहों और पत्रकारों के ही नाम शामिल नहीं हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ़ जस्टिस और वर्तमान में बीजेपी से राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला और उससे जुड़े 10 लोगों के नंबर भी इस डेटा बेस लिस्ट का हिस्सा हैं।

पहली बार नहीं सामने आया जासूसी का जिन्न, काफी पुराना है इतिहास

देश में जासूसी कांड की कथा नई नहीं है, राजनीति और जासूसी या फोन टैपिंग का रिश्ता बहुत पुराना है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सांसद, उद्योगपति और सिनेमाई जगत के लोगों के नाम पहले भी आ चुके हैं। आज हम आपको बीते वक्त के कुछ पन्ने पलट कर ऐसे ही जासूसी या फिर कहें कि फोन टैपिंग के किस्से बताने जा रहे हैं। ज्ञानी जैल सिंह ने राष्ट्रपति रहते हुए तत्कालीन पीएम राजीव गांधी पर फोन टैप का आरोप लगाया था। जैल सिंह का कहना था कि राजीव यह जानना चाहते थे कि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के साथ मेरी क्या बातचीत हो रही है।

1988 कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के कार्यकाल में भी फोन टैपिंग का बड़ा मामला सामने आया था, राजनीतिक विरोधियों के फोन टैप करने के आरोप में कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े को इस्तीफा देना पड़ा था।

1990 चंद्रशेखर ने तत्कालीन नेशनल फ्रंट की सरकार पर अपना फोन टैप करने का इल्जाम लगाया था।

2006 पूर्व सांसद अमर सिंह ने आईबी से जुड़े कुछ लोगों पर फोन टैप का आरोप लगाया था, अमर सिंह ने केंद्र और सोनिया गांधी पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया था।

2010 उद्योगपतियों रतन टाटा और मुकेश अंबानी की कंपनियों के लिए जनसंपर्क का काम कर चुकीं नीरा राडिया के फोन टैप का मामला सामने आया, लेख में दावा किया गया था कि उद्योग जगत के लोग, नेताओं और मीडियाकर्मियों ने ए राजा को दूरसंचार मंत्री बनाए रखने के लिए गोलबंदी की थी।

2010 तत्कालीन यूपीए सरकार ने देश के कुछ शीर्ष नेताओं के फोन टैप करवाए, जिसमें तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार, कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सीपीएम के पूर्व महासचिव प्रकाश करात शामिल थे।

2010 तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिखकर जासूसी का शक जताया था। प्रणब ने इस चिट्ठी में अपने मंत्रालय में 16 जगहों पर चिपकाने वाला पदार्थ मिलने की बात कही थी।

आइटी कानून के तहत भारत में कार्यरत कोई भी सोशल साइट या साइबर कंपनी यदि व्यक्ति विशेष या संस्था की कोई गोपनीय जानकारी जुटाना चाहती है तो केंद्र व राज्य सरकार से लिखित अनुमति लेना आवश्यक है। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं, जिससे व्यक्ति की निजता का हनन न हो। ऐसे मामले सामने आने पर सरकार भी, निजता गोपनीय बनी रहे इस सुरक्षा के प्रति प्रतिवद्धता जताती रही है। वैसे सरकारों द्वारा अपने विरोधियों के टेप करने के मामले जब तक

सामने आते ही रहते हैं। कांग्रेस ने 2011 में डॉ. मनमोहन सिंह सरकार में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा और राजनीतिक लॉबिस्ट नीरा राड़िया की बातचीत का टेप लीक हुआ था। कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार पर यह बड़ा संकट था। अरूण जेटली ने तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का इस्तीफा तक मांग लिया था।

हालांकि भारत में 10 ऐसी सरकारी गुप्तचर जांच एजेंसियां हैं, जो आधिकारिक रूप से संदिग्ध व्यक्ति अथवा संस्था की जांच कर सकती हैं।

हालांकि भारत में संचार उपकरण से जुड़ा पहला बड़ा मामला राष्ट्रपति ज्ञानी जैल की जासूसी से जुड़ा है। इस फोन टैपिंग के समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। इस मामले में राष्ट्रपति के पत्रों की जांच करने का आरोप राजीव गांधी सरकार पर लगा था। इसी तरह पूर्व वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी के सरकारी दफ्तर में भी जासूसी यंत्र मिलने की घटना सामने आई थी। इन रहस्यों के उजागर होने से इलेक्ट्रोनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग को लेकर लोगों के मन में संदेह स्वाभाविक है। लिहाजा सरकार को अपनी जबावदेही स्पष्ट करने की जरूरत है। एक तरफ भारत ही नहीं दुनिया की नीतियां ऐसी बनाई जा रही हैं कि नागरिक डिजीटल तकनीक का उपयोग करने के लिए बाध्य हो या फिर स्वेच्छा से करे। दूसरी तरफ सोशल साइट ऐसे ठिकाने हैं, जिन्हें व्यक्ति निजी जिज्ञासा पूर्ति के लिए उपयोग करता है। इस दौरान की गई बातचीत पेगासस सॉफ्टवेयर ही नहीं, कई ऐसे अन्य सॉफ्टवेयर भी हैं जो व्यक्ति की सभी गतिविधियों का क्लोन तैयार कर लेने में सक्षम हैं।

दुनिया भर में ड़ेढ़ करोड़ उपभोक्ताओं वाले

क्या है एमनेस्टी इंटरनेशनल?

एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन स्थित एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, जो गैर-सरकारी संस्था है। इस संगठन की स्थापना 1961 में पीटर बेन्सन नाम के एक वकील ने की थी। जेलों में गलत आरोपों के चलते बंद लोगों की रिहाई के लिए इस संगठन को बनाया गया था। इस संगठन के सदस्य सीन मैकब्राइड को नोबेल पीस पुरस्कार भी मिल चुका है। संगठन का कहना है कि वो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए शोध और जांच करती है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल पर क्यों उठ रहे सवाल?

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दावा किया था कि भारत में कई नेताओं, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत करीब 300 लोगों की जासूसी की गई थी। दुनिया के कई बड़े मीडिया संस्थानों ने एक रिपोर्ट साझा कर दावा किया था कि इजरायल की साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ के पेगासस स्पायवेयर के जरिये कई देशों में 50,000 से यादा लोगों के फोन हैक कर जासूसी को अंजाम दिया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की ओर से ये भी कहा गया था कि उसकी सिक्योरिटी लैब में इस लिस्ट में शामिल कई लोगों के मोबाइल की फॉरेंसिक विश्लेषण कर शोध किया गया, जिसमें ये बात निकल कर सामने आई है। एमनेस्टी इंटरनेशल का दावा था कि जांच में आधे से यादा मामलों में पेगासस स्पायवेयर के निशान मिले थे। हालांकि भारत में इस पेगासस रिपोर्ट के साथ ही इसे साझा करने वाली एमनेस्टी इंटरनेशनल पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। पेगासस जासूसी कांड को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस रिपोर्ट में किए गए अपने दावे से यू-टर्न ले लिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि उसने इस लिस्ट को कभी भी एनएसओ पेगासस स्पायवेयर लिस्ट नहीं कहा। दुनिया के कुछ मीडिया संस्थानों ने ऐसा किया होगा, लेकिन एमनेस्टी ने इस लिस्ट को लेकर साफ किया है कि ये उन लोगों के नाम हो सकते हैं, जिनकी जासूसी कराना एनएसओ के ग्राहक पसंद कर सकते हैं। ये उन लोगों की लिस्ट नहीं थी, जिनकी जासूसी की गई।

वाट्सऐप में सेंध लगाकर पत्रकारों विपक्षी नेताओं, मानवाधिकारों व सामाजिक कार्यकताओं की जासूसी करने के आरोप भी लगे थे, लेकिन इसमें भी कोई प्रमाण अब तक सामने नहीं आए हैं। उस समय फेसबुक के स्वामित्व वाली वाट्सऐप ने स्वयं जानकारी दी थी कि इजरायली स्पाइवेयर पेगासस के मार्फत चार महाद्वीपों में करीब 1400 लोगों के फोनों में सेंध लगाई गई है। इस रहस्योद्घाटन के बाद वाट्सऐप ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित संघीय न्यायालय में एनएसओ समूह के विरुद्ध मुकदमा भी दायर किया हुआ है। इस एफआईआर में वाट्सऐप ने कहा है कि 1400 फोन में स्पाइवेयर पेगासस डालकर उपभोक्ताओं की महत्वपूर्ण जानकारी चुराई गई हैं। हालांकि वाट्सऐप ने कुटिलता बरतते हुए प्रभावितों की संख्या सही नहीं बताई है। यह जानकारी तब चुराई गई थी जब भारत में अप्रैल-मई 2019 में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में विपक्ष ने यह आशंका जताई थी कि इस स्पाइवेयर के जरिए विपक्षी नेताओं और केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्षरत लोगों की अपराधियों की तरह जासूसी

भारत से क्यों समेटना पड़ा बोरिया बिस्तर?

बीते साल सितंबर में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी भारत में स्थित इकाई को बंद कर दिया था। संगठन ने मोदी सरकार पर बदले की भावना से काम करने के आरोप लगाए थे। दरअसल एमनेस्टी इंटरनेशनल पर अवैध रूप से विदेशी चंदा लेने के आरोप लगे थे। मामले की जांच कर रही एजेंसियों ने ये भी पाया था कि विदेशी धन को ये संगठन देश की अन्य एनजीओ को भी बांट रहा था। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर बयान जारी करते हुए कहा था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को सिर्फ एक बार साल 2000 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट के तहत मंज़ूरी मिली थी। इसके बाद के सभी आवेदनों को मंज़ूरी नहीं मिली थी। स्नष्ट नियमों दरकिनार करते हुए संगठन ने विदेशों से चंदा लिया। अवैध तरीकों से धन लेने की वजह से ही एमनेस्टी इंटरनेशनल के आवेदनों को खारिज किया जाता रहा है।

अमेरिका, रूस जैसे कई देशों में एमनेस्टी पर रोक तो भारत में क्यों नहीं?

साल 2016 में रूस ने भी एमनेस्टी इंटरनेशनल के कामों को लेकर उस पर रोक लगा दी थी। रूस, अमेरिका जैसे दर्जनों देशों में किसी भी विदेशी संस्था या संगठन को देश की राजनीति या आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर एक जैसे ही हैं। ये दोनों ही अपने कामों से लोगों के विचारों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यह संगठन अपने विचारों को देश के लोगों पर थोप कर सरकार विरोधी माहौल को बढ़ावा देती हैं और लोगों में असंतोष की भावना को भड़काती हैं। बीते साल ही भारत के गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में मानवीय काम जारी रखने की स्वतंत्रता है। लेकिन विदेशी धन पाने वाले इन संगठनों को भारत की घरेलू राजनीतिक बहस में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है।

आतंकियों से लेकर दिल्ली दंगों तक मानवाधिकार की वकालत

बीते साल दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लंबे समय से चल रहे धरनों के बाद हिंसा भड़क गई थी। दिल्ली में हुए दंगों को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। आसान शब्दों में कहें तो संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में एक तरह से दिल्ली पुलिस पर ही दंगों को भड़काने और उन्हें हवा देने के आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ बर्बरता की थी, जो सीधे तौर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन था। पूरी दुनिया में इस रिपोर्ट की वजह भारत की छवि को काफी धक्का लगा था। वैसे ये इकलौता मामला नहीं है जब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित की हो। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद बवाल की आशंका के चलते नजरबंद किए गए लोगों के मानवाधिकार को लेकर भी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दुनिया भर में भारत की किरकिरी कराने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी थी। इसी रिपोर्ट के सहारे पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की कोशिश करता रहा। इससे इतर मुंबई आतंकी हमले के दोषी अजमल कसाब, संसद हमले के दोषी अफजल गुरु और 1993 मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पूरी दुनिया में अभियान चलाए थे। भीमा कोरेगांव हिंसा को लेकर भी इस संगठन के बयानों से भारत की छवि काफी खराब हुई थी।

कराई गई। हालांकि इस मामले में भी अब तक कोई तथ्यपूर्ण सच्चाई सामने नहीं आई है। वैसे आइटी कानून के तहत भारत में कार्यरत कोई भी सोशल साइट या साइबर कंपनी यदि व्यक्ति विशेष या संस्था की कोई गोपनीय जानकारी जुटाना चाहती है तो केंद्र व राज्य सरकार से लिखित अनुमति लेना आवश्यक है। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं, जिससे व्यक्ति की निजता का हनन न हो। ऐसे मामले सामने आने पर सरकार भी, निजता गोपनीय बनी रहे, इस सुरक्षा के प्रति, प्रतिबद्धता जताती रही है। वैसे सरकारों द्वारा

सवाल जिनके जवाब नहीं मालूम

- क्या भारत सरकार एसएसओ ग्रुप की क्लाइंट है? इस सवाल पर सरकार ने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया है।
- क्या सभी 1571 नंबर जिसके बारे में पेगासस प्रोजेक्ट में जांच की गई है, उनकी हैकिंग हुई है? इसका जवाब नहीं मिल सका है।
- 50 हजार के डेटा बेस में 1571 नंबर जाँच के लिए क्यों और कैसे चुने गए?
- भारत की संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा था। एक दिन पहले ये रिपोर्ट आई, क्या ये महज़ संयोग है?
- कथित जासूसी लिस्ट में शामिल लोगों के बारे में किस तरह की सूचना जमा की जा रही थी?
- लीक डेटा बेस कहाँ से मिले इसकी पुख़्ता जानकारी नहीं है।
- लीक डेटा बेस में भारत के कुल कितने लोग शामिल हैं, इसकी पुख़्ता जानकारी नहीं है।
- एनएसओ जिस जाँच की बात कर रहा है, क्या वो अब संभव है?
- एनएसओ को इस जासूसी स्पाईवेयर के लिए पैसे कौन दे रहा था?

अपने विरोधियों के टेप करने के मामले सामने आते ही रहते हैं।

क्या है वो लॉफ़ुल इंटरसेप्शन जिसकी दुहाई दे रही है भारत सरकार

पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल से भारत के कई पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फ़ोन हैक होने के आरोप पर केंद्र सरकार ने इस बात का जवाब अब तक नहीं दिया है कि क्या भारत सरकार ने इजराइली कंपनी एनएसओ से पेगासस स्पाईवेयर ख़रीदा या नहीं। इसके उलट सरकार ने संसद के ज़रिए देश भर को बताया है कि लॉफ़ुल इंटरसेप्शन या कानूनी तरीके से फ़ोन या इंटरनेट की निगरानी या टैपिंग की देश में एक स्थापित प्रक्रिया है जो बरसों से चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा कि भारत में एक स्थापित प्रया है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य से या किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की घटना होने पर या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए

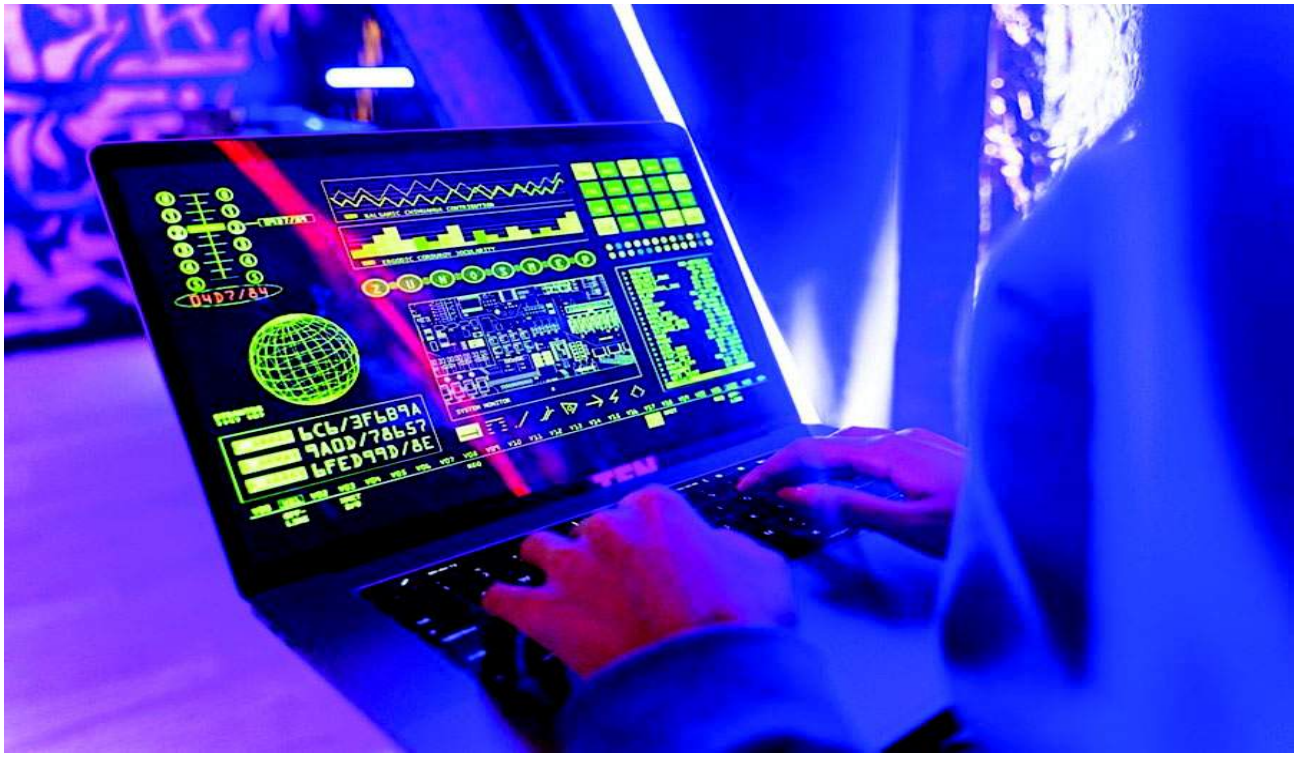

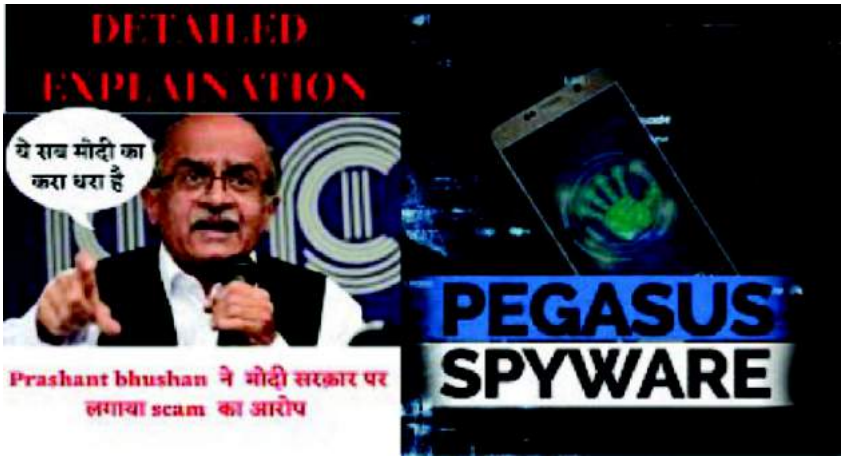

केंद्र और राज्यों की एजेंसियां इलेक्ट्रॉनिक संचार को इंटरसेप्ट करती हैं। 2012 में आरटीआई से जुटाई गई जानकारी के आधार पर रिपोर्ट किया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय औसतन हर दिन 250-300 टेलीफ़ोन इंटरसेप्शन का आदेश देता है और हर महीने औसतन 7,500 से 9,000 टेलीफ़ोन इंटरसेप्शन के आदेश जारी किए जाते हैं। इस ख़बर में बताया गया कि एक बार इजाज़त मिलने के बाद इंटरसेप्शन को दो महीने तक जारी रखा जा सकता है और दो बार रिन्यू किया जा सकता है लेकिन किसी भी स्थिति में ये इंटरसेप्शन 180 दिनों से यादा दिनों तक नहीं किया जा सकता।

क्या कहता है कानून?-

भारत में संचार के इंटरसेप्शन के बारे में आज के वर्तमान परिवेश में अगर देखा जाये तो इंटरसेप्शन को लेकर कानून काफ़ी साफ़ है। इंटरसेप्शन एक वैध गतिविधि है जो हर एक संप्रभु राष्ट्र अपनी अखंडता और सुरक्षा के लिए करता है। लेकिन इंटरसेप्शन चूंकि कहीं न कही लोगों के मौलिक अधिकार के हनन की दिशा में जाता है तो उसे नियंत्रित करने के लिए कानूनी प्रावधान बनाये गए हैं। भारत में पहले 1885 का इंडियन टेलीग्राफ़ एक्ट था जो मुख्य तौर पर टेलीफ़ोन और टेलीग्राफ़ के इंटरसेप्शन से सम्बंधित था लेकिन साल 2000 में भारत ने अपने सूचना प्रौद्योगिकी कानून को लागू किया। इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एक विशेष क़ानून है। इसका सेक्शन 81 कहता है

कहा जा रहा है कि पेगासस जासूसी कांड में उद्योगपति अनिल अंबानी का फोन नंबर भी है।

कि अगर इस कानून के प्रावधानों और अन्य कानूनों के प्रावधानों में कोई भी टकराव होता है तो इस कानून के प्रावधानों को सर्वोपरि माना जाएगा। आईटी एक्ट में सेक्शन 69 में इंटरसेप्शन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया गया जिसमें यह साफ़ कर दिया गया कि अगर सरकार को लगता है कि कुछ वजहों से उन्हें इंटरसेप्शन करनी चाहिए तो वो ऐसा कर सकती है। भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, पड़ोसी देशों के साथ मैत्री सम्बद्ध, शालीनता, नैतिकता या किसी संज्ञेय अपराध को अंजाम देने से रोकने के नाम पर यह हो सकता है। केंद्रीय सरकार किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को भारत में कंप्यूटर सिस्टम्स पर मौजूद किसी भी जानकारी को इंटरसेप्ट करने के दिशा-निर्देश दे सकती है।

क्या भारत में वैध इंटरसेप्शन का कानूनी ढांचा मज़बूत है?

भारत का वर्तमान में इंटरसेप्शन का तंत्र मज़बूत नहीं है। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 69 को 2015 में बनाये रखा लेकिन समस्या यह है कि इंटरसेप्शन के लिए जो वजहें दी गई हैं वो इतनी विशाल और व्यापक हैं कि लगभग दुनिया की हर चीज़ उसके दायरे में आ सकती है। भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा इतने बड़े मापदंड हैं कि इनके तहत लगभग हर चीज़ आ सकती है। धारा 69 में जो पर्याप्त निगरानी और संतुलन होने चाहिए वो मौजूद नहीं हैं और पारदर्शिता नहीं है। तो बात सरकार की मर्ज़ी की बन जाती है। अगर उनकी मर्ज़ी है कि इंटरसेप्ट करना है तो वो करेंगे और कहेंगे कि फलां वजह बन गई। इंटरसेप्ट करने की वजहों को जिस तरह परिभाषित किया गया है उसमे और स्पष्टता लाने की ज़रुरत है कि किन-किन परिस्थितियों में ही आप इंटरसेप्शन कर सकते हैं। भारत में जब निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना जा चुका है तो अगर इंटरसेप्शन से उसका हनन होता है तो सरकार के ख़लिाफ़ मुकदमे दायर होंगे ही। भारत का क़ानूनी ढांचा बहुत मज़बूत नहीं है और मौजूदा कानून के दुरुपयोग की ज़बरदस्त गुंजाइश है।

निश्चित तौर पर पेगासस जासूसी कांड पर जो बबाल सारे देश में मचा है उसका आधार जरूर है क्योंकि यह सीधे तौर पर देश की निजता का सवाल है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मूल्यों पर प्रहार है। इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई भले ही अभी गर्त में हैं लेकिन विपक्ष द्वारा जो आरोप मोदी सरकार पर लगाए जा रहें हैं उससे तो यही लगता है कि देश के अंदर बहुत बड़े स्तर पर जासूसी हुई है। यह जासूसी किसने कराई, क्यों कराई, यह शायद कभी बाहर न आए। सवाल आखिर में वहीं से खड़ा होता है कि जासूसी कराने का प्रमुख उद्देश्य क्या देश हित में है या किसी पार्टी विशेष के लिए है। क्योंकि हमने देखा है कि आजाद भारत के बाद लगभग सभी पार्टियों की सरकारों पर जासूसी कराने के आरोप लगते रहे हैं और आरोप सत्य भी साबित हुए हैं। इन जासूसियों में सिर्फ मकसद सरकारों के ही हित छुपे नजर आए हैं, इनमें देश की सुरक्षा ओर खतरा के बिंदु नदारद रहते हैं। यह बात भी सही है कि जिन कंपनियों या फर्म्स से जासूसी करवाई जाती है। उनसे यह उम्मीद करना भी नासमझी है कि यह जानकारियों देश के बाहर नहीं जाएगी। अंत में यही कहा जा सकता है कि इस तरह जासूसियों से देश में उत्पन्न होने वाले खतरों से बचाने की जिम्मेदारी सत्तासीन सरकारों की ही है। इसलिए जरूरी है कि जासूसी कराने के उद्देश्य देशहित में हो न कि सरकारों के हित में।

पहले हमला, फिर आरोप, उसके बाद हंगामा, अब माफी ये हो रहा है भूपेश सरकार में

क्या टीएस बाबा को ठिकाने लगाने रची जा रही थी बड़ी साजिश?

विजया पाठक

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह पर हमले को लेकर हर दिन नये मोड़ सामने आ रहे हैं। अब बृहस्पति सिंह ने अपने द्वारा लगाए गए आरोपों पर टीएस सिंहदेव से माफी मांग ली है। मतलब पहले हमला, फिर आरोप, उसके बाद हंगामा, अब माफी। भूपेश सरकार में ये चल रहा है। इससे पहले विधायक बृहस्पति सिंह पर हमले में सिंहदेव के रिश्तेदार का नाम सामने आया था। इस मामले को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री और

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह पर हमले को लेकर हर दिन नये मोड़ सामने आ रहे हैं। अब बृहस्पति सिंह ने अपने द्वारा लगाए गए आरोपों पर टीएस सिंहदेव से माफी मांग ली है। मतलब पहले हमला, फिर आरोप, उसके बाद हंगामा, अब माफी। भूपेश सरकार में ये चल रहा है। इससे पहले विधायक बृहस्पति सिंह पर हमले में सिंहदेव के रिश्तेदार का नाम सामने आया था। इस मामले को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ।

स्वास्थ्य मंत्री आमने सामने आ गए। अपनी ही सरकार के विरोध में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सदन का बहिष्कार कर दिया था। टीएस सिंहदेव ने कहा कि रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक पर हुए हमले पर जब तक सरकार जांच का आदेश नहीं देती या बयान नहीं देती तब तक वह खुद को इस प्रतिष्ठित सदन का हिस्सा नहीं बनेंगे। गौरतलब है कि 23 जुलाई की देर रात कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले पर हमला हुआ था। कुछ युवकों ने उनकी गाड़ी रोककर तोड़फोड़ की थी। हमले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के रिश्तेदार का नाम सामने आया था। वहीं विधायक ने आरोप लगाया था कि पार्टी का एक गुट उनसे नाराज है, जिसकी वजह से यह हमला कराया गया। विधायक बृहस्पति सिंह ने कहा था कि बीते दिनों उन्होंने बघेल की प्रशंसा की थी और कहा था कि वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यह बयान स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव को पसंद नहीं आया और बाद में उनके काफिले पर हमला किया गया। कांग्रेस विधायक ने यह भी आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य मंत्री से उनकी जान को खतरा है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव पर हत्या का आरोप लगाने वाले कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह यहीं नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया कि सिंहदेव सरजुगा में हिटलरशाही चलाते हैं। आरोपों को लेकर सिंहदेव ने कहा था कि कुछ लोग

छत्तीसगढ़ विधान सभा में हंगामा

छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच राज्य के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि यह बहुत छोटी बात है। विधायक बृहस्पति सिंह ने दावा किया कि टीएस सिंहदेव उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने आईजी, गृहमंत्री या फिर मुख्यमंत्री के सामने इसकी शिकायत नहीं की। भावनाओं में बहकर उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर यह आरोप लगाया होगा। विधानसभा के पहले दिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया दिन भर अपनी पार्टी के विधायकों एवं मंत्रियों को मनाने समझाने में लगे रहे

उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके क्षेत्र और राज्य के लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं।

वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच राज्य के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि यह बहुत छोटी बात है। विधायक बृहस्पति सिंह ने दावा किया कि टीएस सिंहदेव उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने आईजी, गृहमंत्री या फिर मुख्यमंत्री के सामने इसकी शिकायत नहीं की। भावनाओं में बहकर उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर यह आरोप लगाया होगा। विधानसभा के पहले दिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया दिन भर अपनी पार्टी के विधायकों एवं मंत्रियों को मनाने समझाने में लगे रहे, यहां तक कि

अमित जोगी ने इस मसले पर कहा कि इतिहास दोहरा रहा है। अगर हम अपनी ग़लतियों से नहीं सीखेंगे तो जिस प्रकार से मेरे स्वर्गीय पिताजी अजीत जोगी और मुझे झीरम कांड में घसीटने का षड़यंत्र हुआ था, उसी तरह टीएस सिंहदेव को भी झूठ के जंजाल में फ़ंसाने की कोशिश हो रही है। घटिया राजनीति करने वालों को बेनकाब होगा। बृहस्पति सिंह का खुद का कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। 2013 में मेरे पिता जी की कृपा से वे तत्कालीन गृहमंत्री रामविचार नेताम के ख़िलाफ़ चुनाव लड़े और जीते।

दिल्ली रवाना होने के लिए निकले और एयरपोर्ट से वापस भी लौटे पर फिर भी मामला किसी नतीजे पर पहुंचता दिखाई नहीं दिया। वहीं विधानसभा के दूसरे दिन भी जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो टी.एस. सिंहदेव सदन से बाहर आये। उन्हें मुख्यमंत्री ने अपने चेंबर में बुलाया। हालांकि अंदर किस बात पर चर्चा हुई इस पर मीडिया से उन्होंने कुछ नहीं बताया। गौरतलब है कि उसी दिन राजधानी रायपुर में कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बड़ी बैठक शुरू हुई। दिन में हुई बैठक के बाद देर शाम कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के बड़े हमले से प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया था। अमित जोगी ने इस मसले पर कहा कि इतिहास दोहरा रहा है। अगर हम अपनी ग़लतियों से नहीं सीखेंगे तो जिस प्रकार से मेरे स्वर्गीय पिताजी अजीत जोगी और मुझे झीरम कांड में घसीटने का षड़यंत्र हुआ था, उसी तरह टीएस सिंहदेव को भी झूठ के जंजाल में फ़ंसाने की कोशिश हो रही है। घटिया राजनीति करने वालों को बेनकाब होगा। बृहस्पति सिंह का खुद का कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। 2013 में मेरे पिता जी की कृपा से वे तत्कालीन गृहमंत्री रामविचार नेताम के ख़िलाफ़ चुनाव लड़े और जीते।

बृहस्पति सिंह पहले से ही काफी विवाद करते रहे हैं। बोलते हैं कि वे छत्तीसगढ़ के नहीं बिहार के निवासी हैं। बृहस्पति सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने खड़ा किया था। बृहस्पति सिंह इसके पहले भी बलरामपुर के कलेक्टर एस. एल. पाल मेनन पर भी अपनी हत्या कराने का आरोप लगा चुके हैं। बृहस्पति सिंह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चहेते विधायक हैं।

आपको बता दें कि बृहस्पति सिंह पहले से ही काफी विवाद करते रहे हैं। बोलते हैं कि वे छत्तीसगढ़ के नहीं बिहार के निवासी हैं। बृहस्पति सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने खड़ा किया था। बृहस्पति सिंह इसके पहले भी बलरामपुर के कलेक्टर एस. एल. पाल मेनन पर भी अपनी हत्या कराने का आरोप लगा चुके हैं। बृहस्पति सिंह मुख्यमंत्री भूपेश

बघेल के चहेते विधायक हैं। प्रदेश में चर्चा है कि बृहस्पति सिंह का उपयोग किया जा रहा है। कहीं ना कहीं यह मसला ढाई-ढाई साल के मुख्यमंत्री से जुड़ा है। पूरा प्रदेश ही नहीं कांग्रेस हाईकमान भी जानता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के संबंध अच्छे नहीं हैं। स्वास्थ्य विभाग की कई बैठकों में विभागीय मंत्री को नहीं बुलाया जाता है। यह भी सत्या है कि पूरे विवाद की जड़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया हैं, जो कई वर्षो से प्रदेश में जमे हुए हैं। वह मुख्यमंत्री बघेल का समर्थन करते हैं। यह किसी से छुपा नहीं है।

आखिर विधायक बृहस्पति सिंह ने किसकी शह पर टीएस सिंहदेव पर इतने गंभीर आरोप लगाए थे। मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्री मंडल मौन था। यदि उनके आरोप में सच्चाई थी तो बृहस्पति सिंह को यह बात अपने पार्टी फोरम, प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री के सामने रखना था लेकिन उन्होंकने सबसे पहले प्रेस

बृहस्पति सिंह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चहेते विधायक हैं। प्रदेश में चर्चा है कि बृहस्पति सिंह का उपयोग किया जा रहा है। कहीं ना कहीं यह मसला ढाई-ढाई साल के मुख्यमंत्री से जुड़ा है। पूरा प्रदेश ही नहीं कांग्रेस हाईकमान भी जानता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के संबंध अच्छे नहीं हैं।

कांफ्रेंस करके सारी झूठी बातें मीडिया से सामने रखी। इससे जाहिर होता है कि उनके मन में कुछ तो चल रहा था। अपनी ही सरकार के मंत्री पर हत्या कराने जैसा आरोप लगाकर उन्होंने अनुशासनहीनता की पराकाष्ठाज पार की है। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय नेता टीएस सिंहदेव प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही सुर्खियों में आ गए थे। लोगों को उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ही बनेंगे। किंतु कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भूपेश बघेल पर विश्वास जताते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद ढाई-ढाई साल के फार्मूले पर भी खूब चर्चा हुई। किंतु ढाई साल बाद टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बजाय उनको ठिकाने लगाने के लिए कांग्रेसियों ने ही उनके लिए गड्ढा खोदना शुरू कर दिया है।

जिस तरह कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह टीएस सिंहदेव पर उनके द्वारा उनकी हत्या करवाने का आरोप लगा रहे हैं, उससे यह साबित होता है कि बृहस्पति सिंह से षड्यंत्र के तहत एक बड़ी साजिश को अंजाम दिलाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले में सोचने वाली बात यह है कि अभी तक कांग्रेस का संगठन एवं उच्च नेतृत्व पूरी

तरह मौन साधे हुए है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस पूरे मामले में चुप्पी साधकर बैठे हैं। टी.एस. सिंहदेव एक सिद्धांतवादी, मिलनसार, निर्विवाद नेता के रुप में जाने जाते हैं लेकिन कांग्रेस सरकार में इनकी जिस तरह से उपेक्षा की जा रही है उससे सिंहदेव इस्तीफा देने की मूड पर रहे हैं परंतु इस्तीफा न देकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी का सम्मान किए जाने की बात इनके समर्थक करते हैं लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के विधायक ने जानलेवा हमला करने की बात कही है उससे टी.एस. सिंहदेव की छवि धूमिल करने का प्रयास किए जाने की बात कहीं जा रही है और यह चर्चा होने लगी है कि कभी भी सिंहदेव मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टीएस बाबा को किस तरह से किनारे किया है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। निगम मंडलों, आयोगों में इनके समर्थकों को जगह नहीं देने, स्वास्थ्य विभाग में भाजपा सरकार के वक्त हुए नान घोटाले के चर्चित आरोपी डॉ. आलोक शुक्ला को सेवावृद्धिं देकर इनके बिना सहमति के प्रमुख सचिव बनाए जाने सहित अन्य तरह से टीएस बाबा पूरी तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से खफा हैं और विधायक बृहस्पति सिंह द्वारा इस तरह से आरोप लगाए जाने से टी.एस. सिंहदेव पूरी तरह से आहत हो चुके थे।

कांग्रेस पार्टी हाईकमान को छत्तीसगढ़ में मचे घमासान पर एक्शन लेना चाहिए। क्यों कि वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है उससे कांग्रेस को काफी नुकसान हो सकता है। खासकर ढाई-ढाई साल के फार्मूले पर हाईकमान को जरूर विचार करना चाहिए। क्योंकि राज्य में कलह की प्रमुख वजह यही फार्मूला पर कार्य नहीं होना है। इससे पार्टी के अंदर गुटबाजी हावी होती जा रही है। यदि राज्यों में ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 2023 के चुनाव में कांग्रेस को काफी परेशानी हो सकती है। ढाई-ढाई साल के फार्मूले पर मुकरने से वैसे भी कांग्रेस की छबि काफी धूमिल हुई है। मौजूदा मुख्यमंत्री से प्रदेश की जनता काफी त्राहिमाम है। सभी क्षेत्रों में तानाशाही चल रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है। लोकतांत्रिक मूल्यों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। मीडिया पर पाबंदी, अफसरों पर नकेल कसना जैसे काम धड़ल्ले से हो रहे हैं। ऐसे हालातों में हाईकमान को मुख्यमंत्री को बदलना पार्टी के हित में लिया गया फैसला साबित होगा।

दांव पर यरूशलम

मध्यपूर्व में इजराइल की बढ़ती सामरिक ताकत अरबराष्ट्रवाद को चुनौती देती रही है। इस्लामिक नेतृत्व को लेकर अरब राष्ट्रों की आपसी प्रतिद्वंद्विता ने भी इजराइल को ताकत दी है। इजराइल को रणनीतिक रूप से घेरने वाले देश आंतरिक अशांति और राजसत्ता की अपनी मजबूरियों से जूझ रहे हैं।

ब्रह्मदीप अलूने

मशहूर जर्मन सैन्य विशेषज्ञ क्लाजविट्ज ने कहा था कि राज्य अपनी नीतियों को लागू करने के लिए युद्ध का सहारा लेते हैं। मध्य पूर्व में इजराइल और फिलस्तीन की नीतियां बेहद साफ हैं। इजराइल का अस्तित्व यहूदियों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है, वहीं फिलस्तीनियों और अरब के नजरिए से इजराइल का खत्म होना जरूरी है। दुनिया के बेहद अशांत माने जाने वाले मध्यपूर्व के इजराइल और फिलस्तीन के कई इलाके इस समय दोनों ओर से भयानक हमलों का सामना कर रहे हैं। इससे मध्यपूर्व में हिंसा और तेज होने की आशंका गहरा गई है। इस विवाद को दो प्रमुख स यताओं के संघर्ष के रूप में भी प्रचारित किया जाता रहा है और इसीलिए पूरी दुनिया में इसका असर होता है। पूर्वी भूमध्य सागर के आखिरी छोर परस्थित

इजराइल उत्तर में लेबनान, उत्तर-पूर्व मेंसीरिया, पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम मेंमिस्र से घिरा है। वर्ष 1967 में जब जॉर्डन, सीरिया और इराक सहित आधा दर्जन मुसलिम देशों ने एक साथ इजराइल परहमला किया था तो उसने पलटवार करते ही मात्र छह दिनों में इन सभी देशों को धूल चटादी थी। उस घाव से अरब देश अब भी नहीं उबर पाएं हैं। यह युद्ध पांच जून से ग्यारहजून 1967 तक चला था। इसने मध्यपूर्व संघर्ष का स्वरूप बदल डाला। इतिहास में इस घटना को सिक्स वार डे के नाम से जाना जाता है। इजराइल ने मिस्र को गाजा से, सीरिया को गोलन पहाड़ियों से और जॉर्डन को पश्चिमी तट व पूर्वीयरूशलम से खदेड़ दिया था। इस युद्ध में करीब पांच लाख फिलस्तीनी बेघर हो गए थे। जीते गए इलाके अब इजराइल के कब्जे में हैं। खाड़ी देशों के लगातार दबावों के बावजूद इजराइल इन इलाकों को छोड़ने को तैयार नहीं है। वह पूर्वी यरूशलम के इलाके सहित पूरेयरूशलम शहर को अपनी राजधानी मानता है। जबकि फिलस्तीनी पूर्वी यरूशलम को भविष्य के एक आजाद मुल्क की राजधानी के तौर पर देखते हैं। इन इलाकों में यहूदी बस्तियां बसाकर इजराइल अपनी स्थिति को मजबूत करता जा रहा है, जबकि फिलस्तीनी अपने घरों को किसी भी हालात में छोड़ने को तैयार नहीं है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथास्थितिवाद का सिद्धांत शक्ति संतुलन के साथ शांति की स्थापना को भी सुनिश्चित करता है। लेकिन यथास्थितिवाद को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है और यह किसी भी समयशक्ति संघर्ष का कारण बन जाती है। इजराइल और फिलस्तीन को लेकर दुनिया के कई देश यथास्थितिवाद को पसंद करते हैं, जबकि मध्यपूर्वकी भू-राजनीतिक स्थिति इसकी इजाजत नहीं देती। यरूशलम न केवल राजनीतिक और सामरिकदृष्टि से बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्त्वपूर्ण है। यहांमुसलमानों की पवित्र अल-अक्सा मस्जिद है, जिसे यहूदी टेंपल माउंट कहते हैं। वर्ष 2016 में यूनेस्को ने कहा था कि यरूशलम में मौजूद ऐतिहासिक अल-अक्सामस्जिद पर यहूदियों का कोई दावा नहीं है। यूनेस्को की इस बात को मानने से इजराइल ने इनकार कर दिया था। अल-अक्सा मस्जिद में बड़ी संख्या में मुसलमान आना चाहते हैं, लेकिन इजराइल बलपूर्वक इन्हें रोकता रहा है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। ईद पर बड़ी सं या में मुस्लिम अल-अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहते थे। लेकिनइजराइल ने उन्हें रोक दिया और वहां

वर्ष 2016 में यूनेस्को ने कहा था कि यरूशलम में मौजूद ऐतिहासिक अल-अक्सामस्जिद पर यहूदियों का कोई दावा नहीं है। यूनेस्को की इस बात को मानने से इजराइल ने इनकार कर दिया था। अल-अक्सा मस्जिद में बड़ी संख्या में मुसलमान आना चाहते हैं, लेकिन इजराइल बलपूर्वक इन्हें रोकता रहा है।

से खदेड़ दिया। मध्यपूर्व में इजराइल की बढ़ती सामरिक ताकत अरब राष्ट्रवाद को चुनौती देती रही है। इस्लामिक नेतृत्व को लेकर अरबराष्ट्रों की आपसी प्रतिद्वंद्विता ने भी इजराइल को ताकत दी है। इजराइल को रणनीतिकरूप से घेरने वाले देश आंतरिक अशांति और राजसत्ता की अपनी मजबूरियों से जूझ रहेहैं। इजराइल के उत्तर में लेबनान और पूर्व में सीरिया है। ये दोनों देश गृहयुद्ध से प्रभावित हैं। जबकि उसके दूसरे पड़ोसी जॉर्डन और मिस्र 1967 के इजराइल-अरब युद्ध के बाद यहूदी राष्ट्र के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर खामोश हैं। इन सबके बीच इजराइल को मध्य पूर्व से खत्म कर अरब राष्ट्रवाद की अगुवाई के स्वप्न ने ही इस्लामिक दुनिया को दो भागों में बांट दियाहै। इजराइल-फिलस्तीन विवाद की परछाई में शिया बाहुल्य ईरान ने लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्ला को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद देकर इजराइल पर हमलाकरने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया, वहीं सुन्नी बाहुल्य सऊदी अरब ने हमास को हथियार देकर इजराइल कोनिशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन इस्लामिक दुनिया में बादशाहत कायम रखने के लिएईरान और सऊदी अरब इजराइल को निशाना बनाते-बनाते आपसी हितों के लिए कालांतर में एकदूसरे के ही प्रतिद्वंद्वी बन गए। इस्लामिक देशों के संगठन (ओआइसी) के कई सदस्य देशों के साथ इजराइल के बेहतर संबंध हैं। शिया-सुन्नी विवाद का साया भी ओआइसी पर पड़ता रहा है। तुर्की और सऊदी अरब के बीच इस समय इस्लामिक दुनिया कानेतृत्व करने की होड़ मची है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोआन इजराइल कीआलोचना तो कर रहे हैं, लेकिन वे इजराइल की राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक शक्ति को भलीभांति जानते हैं। एर्दोआन की नीतियां अमेरिका के निशाने पर हैं और उन्हें अपनी स्थिति मजबूत रखने के लिए अमेरिका सेबेहतर रिश्तों की जरूरत है। इसमें उनका बड़ा मददगार इजराइल हो सकता है। दरअसलतुर्की के लिए कुर्द बड़ी समस्या हैं। कुर्द मध्यपूर्व का चौथे सबसे बड़ा जातीय समूह है। इनकी सं या करीब साढ़े तीन करो? से यादा है। वर्तमान में मध्यपूर्व का यहबेहद प्रभावशाली समुदाय है जो नस्ल, भाषा और संस्कृति के आधार पर विभिन्न

देशों में एक दूसरे का सहयोगकर रहे हैं। कुर्दो का अभी कोई एक देश नहीं है। ये तुर्की में अपनी स्वायत्तता के लिए लड़ रहे हैं, तो सीरिया और इराक में अपनी अहम भूमिका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये इस्लामिक स्टेट (आइएस) का भी प्रतिरोध करते रहे हैं। दक्षिणी-पूर्वी तुर्की, उत्तरी-पूर्वी सीरिया, उत्तरी इराक, उत्तर-पूर्वी ईरान और दक्षिण-पश्चिमी आर्मेनिया तक कुर्द फैले हुए हैं। इनको लेकर अमेरिका का रुख भी की उदार ही रहा है। जाहिर है, एर्दोआन ऐसी किसी भी हिमाकत से बचेंगे जिससे अमेरिका और इजराइल नाराज हो जाएं और कुर्द समस्या तुर्की की एकता औरअखंडता के लिए बड़ी चुनौती पेश करने लगे। यूरोप के कई देश भी मध्यपूर्व में अशांति बने रहना हितकर समझते हैं। उन्हें लगता है कि यदि इस इलाके में शांति स्थापित हो जाएगी तो अरब राष्ट्रवाद मजबूत होकर यूरोप को चुनौती दे सकता है। और यदि यूरोप को मध्यपूर्व से तेल मिलना बंद हो गया तो उसके अधिकांश उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे और इस प्रकार दुनिया के सबसे बड़े विकसित यूरोप महाद्वीप की औद्योगिक औरसामरिक क्षमता बर्बाद हो जाएगी। यही कारण है कि पश्चिमी देश मध्यपूर्व पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं और वे मध्य-पूर्व में एक ठिकाने के रूप में इजराइल को सबसे सुरक्षित देश मानते हैं। मध्यपूर्व में बड़ी प्रतिद्वंदिता ईरान और सऊदी अरब की रही है। ईरान को रोकने के लिए सऊदी अरब इजराइल को बेहतर विकल्प मानता है और इन दोनों देशों के बीच गोपनीय भागीदारी भी सामने आई है। सऊदीअरब अपने पारंपरिक और सामरिक मित्र अमेरिका की मध्यपूर्व की नीतियों का एकतरफाविरोध नहीं कर सकता। अत सऊदी अरब का इजराइल विरोध शब्दों से आगे जाए, इसकी कोई संभावना नहीं है। इसके साथ ही सऊदी अरब कोई ऐसा कदम उठानेसे भी बचना चाहेगा जिससे उसके कड़े प्रतिद्वंद्वी ईरान को किसी भी प्रकार से मजबूतीमिल सके।बहरहाल, इजराइल और फिलस्तीन के विवाद में जटिल संतुलन कासिद्धांत हावी है, जिसमें राष्ट्र या राष्ट्र समूह एक दूसरे को संतुलितकरते हैं और फिर संतुलनों के भीतर संतुलन होता है। आने वाले दिनों में इस क्षेत्रमें वैश्विक प्रयासों की बदौलत आधे-अधूरे समझौतों पर आधारित शांति एक बार स्थापितहो जाएगी। इस विवाद से विश्व के कई ताकतवर देशों के व्यापक आर्थिक और सामरिक हितजुड़े हैं। इसलिए फिलस्तीन के नए राष्ट्र का सपना पूरा होने की संभावना दूर-दूर तककहीं नजर नहीं आती है।

नवजोत सिंह सिद्धू को मिली पंजाब कांग्रेस की कमान

कांग्रेस आलाकमान का क्षत्रपों को कड़ा संदेश

मणिशंकर पाण्डेय

आखिर लंबी जद्दोजहद और रस्साकसी के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। इसके साथ ही चार कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। इसमें संगत सिंह, कुलजीत नागरा, पवन गोयल और सुखविंदर डैनी का नाम शामिल हैं। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सिद्धू के सामने कई तरह की चुनौतियां होंगी, जिसका उन्हें सामना करना होगा। इसके साथ ही अब साफ हो गया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और राज्य में कांग्रेस की कमान नवजोत सिंह सिद्दू के हाथ होगी लेकिन इससे विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर सोनिया गांधी से खुलकर नाराजगी जाहिर की थी और पत्र लिखकर कहा था कि इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। इससे पहले पंजाब इकाई में संभावित फेरबदल से पहले 10 कांग्रेस विधायकों ने सीएम अमरिंदर सिंह के पक्ष में बयान देकर एक संयुक्त बयान जारी किया था। इसमें अहम यह है कि अब तक कांग्रेस से जब भी कोई मुख्यमंत्री या अध्यक्ष बनाया जाता है तो प्रदेश कार्यकारिणी सोनिया गांधी के नाम पत्र लिखती है लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रदेश कार्यकारिणी बैठक बुला रही है और अध्यक्ष का ऐलान हो गया। पंजाब कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी ने बैठक बुलाई थी जिसमें आलाकमान के फैसले पर मंजूरी की बात पर फैसला था लेकिन इससे पहले दिल्ली से सिद्धू के नाम का ऐलान हो गया।

पिछले कई दिनों से अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू दोनों एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे थे और समर्थकों की लामबंदी जारी थी। दोनों गुटों में खुलकर सामने आ गए थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान कर चर्चाओं पर जरूर विराम लगा दिया लेकिन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी में गुटबाजी बढ़ने की संभावनाएं जरूर बढ़ गई हैं। संकेत यह

भी हैं कि अगले साल का चुनाव अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और संभव है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने के थोड़े समय के बाद वह इस्तीफा दे देंगे। पर अमरिंदर सिंह से यह उम्मीद करना थोड़ा ज्यादा ही आशावादी होने जैसा है, क्योंकि 2017 के चुनाव में उन्होंने जनता में ऐलान किया था कि वह उनका आखिरी चुनाव होगा और अब वह उससे मुकर चुके हैं। अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती और अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने तो फिर उनसे स्वेखच्छा से पद त्याग करने की उम्मीद करना चांद को धरती पर उतारने के जैसा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर पंजाब में अमरिन्दर सिंह और राजस्थान में अशोक गहलोत को सबसे बड़ा क्षत्रप और जनाधार वाला नेता माना जाता है। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं रह गया है। दिल्ली आलाकमान नहीं चाहता था कि पंजाब में कोई भी कलह के चलते पार्टी को नुकसान हो। क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू अपनी छवि और भाषणबाजी के चलते आम लोगों में काफी लोकप्रिय है। दूसरा सवाल ये है कि पंजाब में अमरिंदर के बाद कौन, इस सवाल का भी आलाकमान ने जवाब दे दिया है। सोनिया गांधी को ना चाहते हुए भी अमरिंदर की मांगों को दरकिनार करना पड़ा और कैप्टन को न चाहते हुए भी कांग्रेस आलाकमान की मर्जी के आगे सिद्धू की ताजपोशी स्वीकार करनी पड़ी! हालांकि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान दिए जाने के बाद अमरिंदर सिंह का कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। वहीं अमरिंदर सिंह की ओर से पटियाला के एक होटल में सियासी दावत रखी गई है जिसका बुलावा सिद्धू को नहीं दिया गया।

कांग्रेस आलाकमान का क्षत्रपों को कड़ा संदेश- मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के कड़े विरोध के बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त कर सोनिया गांधी ने कांग्रेस आलाकमान के अब भी मजबूत होने का संदेश दिया है। साथ ही सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्रियों को खुद पर लगाम लगाने का संदेश दिया है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि अमरिंदर सिंह के साथ महीनों की बातचीत और समझाइश बेकार साबित हुई, इसलिए आलाकमान ने आखिरकार अपना फैसला लिया। पंजाब में आलाकमान की यह कार्रवाई पार्टी के राज्य क्षत्रपों के साथ-साथ सभी मुख्यमंत्रियों के लिए एक संदेश है जो खुद को मुखर कर रहे हैं।

रिश्तों में खींचतान पुरानी- सिद्धू और सिंह के बीच की लड़ाई 2017 में पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनते ही शुरू हो गई थी। अमरिंदर 2017 के विधानसभा चुनाव के समय सिद्धू को कांग्रेस में लाने के पक्ष में नहीं थे। शायद अमरिंदर सिद्धू को अपने ख़िलाफ़

एक चुनौती के रूप में देख रहे थे, लेकिन यह साफ़ था कि सिद्धू का कांग्रेस में प्रवेश गाँधी परिवार के आशीर्वाद से हुआ था और 2017 का चुनाव जीतने पर अमरिंदर सिंह को सिद्धू को कैबिनेट मंत्री बनाना पड़ा। दोनों के बीच की खींचतान तब बढ़ी जब सिद्धू में यह घोषणा की कि वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। अमरिंदर ने सिद्धू को इस बात पर पुनर्विचार करने की सलाह दी लेकिन उस सलाह को दरकिनार करते हुए सिद्धू वाघा बॉर्डर पार कर उस समारोह का हिस्सा बनने के लिए गए। मामला पेचीदा तब हो गया जब अमरिंदर ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जावेद बाजवा के साथ सिद्धू के गले मिलने की खुली आलोचना की। सिद्धू पंजाब में कैबिनेट मंत्री तो बन गए लेकिन ये सिर्फ़ उनकी मुश्किलों की शुरुआत थी। बादल परिवार के केबल टीवी व्यवसाय को निशाना बनाते हुए एक नया कानून लाने की सिद्धू की कोशिश को उन्हीं की सरकार से कोई ख़ास समर्थन नहीं मिला। 2018 में सिद्धू को एक बड़ा झटका तब मिला जब पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस फ़ैसले का समर्थन किया जिसमें 1998 के रोड रेज़ मामले में सिद्धू को दोषी ठहराया गया था और तीन साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। 2019 के लोकसभा चुनावों में आठ संसदीय सीटें जीतने के बाद अमरिंदर सिंह का राजनीतिक क़द और बढ़ा और उन्होंने सिद्धू पर सीधा निशाना साधना शुरू किया। यहाँ तक कि अमरिंदर ने सिद्धू को एक नॉन-परफ़ॉर्मर तक कह डाला और उनसे स्थानीय निकाय विभाग वापस ले लिया गया। सिद्धू ने कांग्रेस आलाक़मान से अपनी नज़दीकी का इस्तेमाल करते हुए अमरिंदर के साथ चल रहे उनके झगड़े को गाँधी परिवार के सामने के रखा पर आख़िरकार उन्हें 2019 में अमरिंदर कैबिनेट से इस्तीफ़ा देना पड़ा। अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच की तल्ख़ी बढ़ने के पीछे सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र से टिकट न मिलना भी एक वजह माना जा रहा है। सिद्धू चंडीगढ़ सीट से पवन कुमार बंसल को हटाकर अपनी पत्नी नवजोत कौर को टिकट दिलाना चाहते थे. अपनी पत्नी को टिकट नहीं मिलने के लिए सिद्धू एक तरह से अमरिंदर सिंह को ही ज़िम्मेदार मानते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह हालांकि इस बारे में स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि सिद्धू अच्छी तरह से जानते हैं कि टिकट देने या नहीं देने का निर्णय केंद्रीय नेतृत्व का है, लेकिन सिद्धू इस पर सहमत नहीं हैं।

अमरिंदर का राजनीतिक कद- 2014 में जब ऐसी धारणा बन रही थी कि कांग्रेस के बड़े नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से कतरा रहे

हैं, उस समय भी सोनिया गाँधी के कहने पर अमरिंदर ने अरुण जेटली के ख़िलाफ़ अमृतसर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हामी भरी और अंततः जेटली को हराया। ये चुनाव लड़ने के समय अमरिंदर पंजाब विधानसभा में विधायक थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने पंजाब में कुल 117 सीटों में से 77 सीटों पर जीत हासिल कर सत्ता में 10 साल बाद वापसी की थी। अमरिंदर सिंह की यह जीत इस मायने में बेहद अहम थी कि 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद बीजेपी लगातार कई राज्यों में अपनी सरकार बनाती जा रही थी। इनमें हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल थे, लेकिन पंजाब की सत्ता में कांग्रेस की वापसी कर अमरिंदर सिंह बीजेपी की विजय रथ को रोकने वाले गिनती के नेताओं में शुमार हो गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में हर तरफ़ मोदी लहर की ही चर्चा थी। यह नतीजों ने भी साफ़ दिखा और जनादेश स्पष्ट रूप से बीजेपी को मिला। लेकिन मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस ने पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 8 सीटें जीतीं और इससे अमरिंदर का कद और ऊंचा हो गया।

विवाद का चुनाव पर असर- 2017 के पंजाब चुनाव के समय अमरिंदर ने धमकी दी थी कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो वे पार्टी तोड़ देंगे। वे फिर वही कर सकते हैं। 2016 के अंत में एक समय ऐसा लग रहा था कि आप पंजाब का चुनाव जीत भी सकती है लेकिन 2017 में अमरिंदर का जीतना इसलिए भी संभव हुआ क्योंकि आप ने कई गड़बड़ियां कीं। आप नेताओं पर खालिस्तानियों से पैसे लेने के आरोप लगे। इससे हिन्दू वोट कांग्रेस की तरफ़ चले गए। आप ने टिकट देने में भी गड़बड़ी की। सबसे बड़ी बात ये हुई कि अरविन्द केजरीवाल ख़ुद ही चुनाव अभियान का चेहरा बन गए।

पायलट और गहलोत का स्कोर कार्ड और भविष्य

पंजाब के बाद क्या राजस्थान में भी बदलेगा हवाओं का रुख?

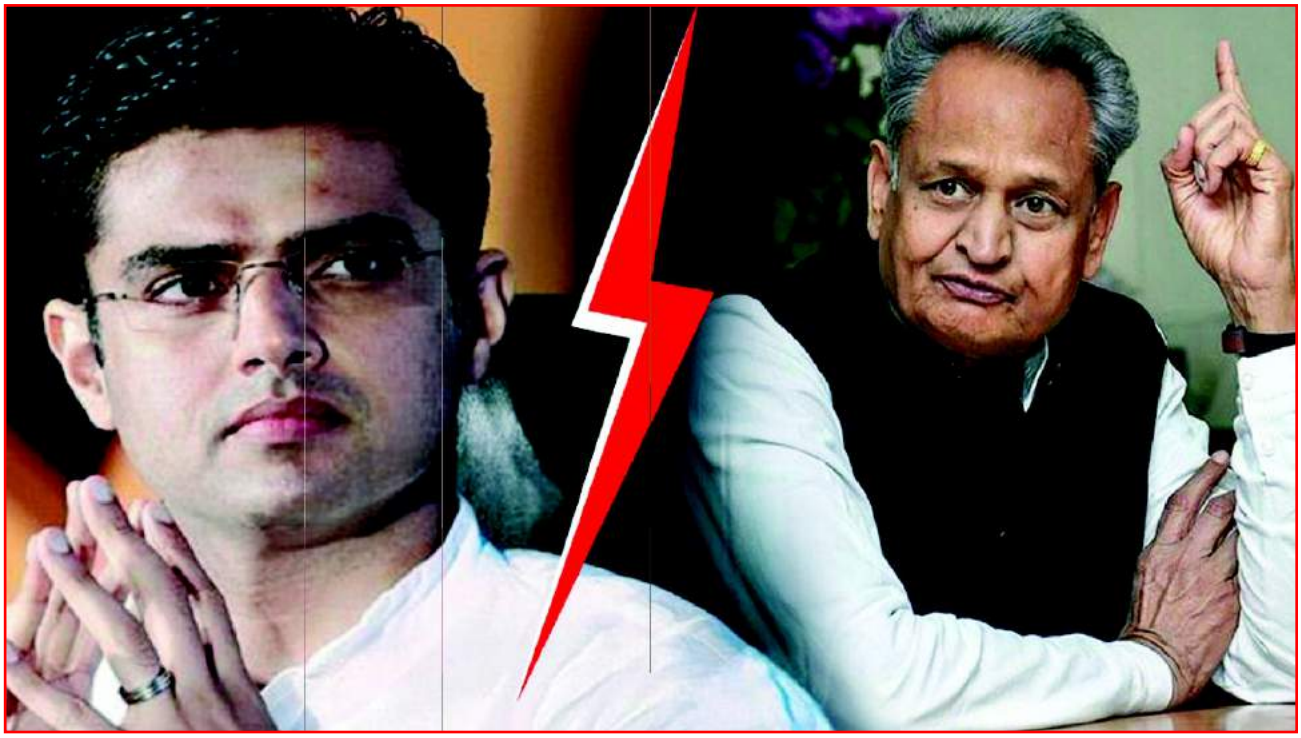

शैफाली दुबे

राजस्थान में कांग्रेस के अंदर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अशोक गहलोत खेमे और सचिन पायलट गुट में खींचतान के बीच शह और मात का खेल जारी है तो आए दिन सियासत का यह खेल नए मोड़ ले रहा है। अब ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि अशोक गहलोत के खेमे में सचिन पायलट सेंध लगाने की कोशिश में हैं। बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कांग्रेस से हाथ मिलाने वाले विधायकों से सचिन पायलट ने फोन पर बात की है। जिसके बाद बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों के खेमे में खलबली मची हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि विधायकों को मजबूती से लड़ाई लड़ने की नसीहत दी गई है। गौरतलब है कि जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद से राजस्थान कांग्रेस में हलचल पैदा हो गई। सचिन पायलट ने कांग्रेस आलाकमान पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उनके बीजेपी में जाने की अटकलों ने जोर पकड़ लिया। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों ने पार्टी आलाकमान को अल्टीमेटम दिया कि या तो जुलाई तक मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां करने का वादा पूरा करो, नहीं तो वे आगे निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। जिसके बाद राजस्थान में फिर से राजनीतिक नाटक शुरू हो गया। सचिन लगातार कांग्रेस आलाकमान पर वो वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं, जो राजस्थान में चुनाव के वक्त पायलट खेमे के लिए किए गए थे।

ऐसे में पायलट गुट लगातार अल्टीमेटम दे रहा है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किल ये है कि सीएम रहते हुए उनकी अगुवाई में 2003 और 2013 में दो विधानसभा चुनाव पार्टी ने लड़े थे। दोनों में करारी शिकस्त मिली थी, लेकिन समय-समय पर गहलोत ने अपने राजनीति के अनुभव को साबित किया है। वहीं सीएम गहलोत हमेशा से गांधी परिवार के खासकर सोनिया गांधी के खास सिपहसालार रहे हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी ने

सचिन पायलट की अगुवाई में 2018 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और लोकसभा उपचुनाव में पार्टी चुनाव जीत कर सत्ता में आई। लेकिन लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें हारी भी थीं। सचिन पायलट एक बार अजमेर से एमपी का चुनाव भी हार चुके हैं, लेकिन एक मास लीडर के रूप में पायलट राजस्थान हीं नहीं हिंदी बेल्ट के साथ अन्य राज्यों में भी लोकप्रिय माने जाने जाते हैं। राजस्थान में लगभग सभी जातियों और खासकर युवाओं में पायलट को लेकर खासा क्रेज है। ऐसे में जब 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के चेहरे पर चर्चा होगी। युवा सचिन पायलट एक बार फिर अशोक गहलोत के सामने चुनौती होंगे तो कांग्रेस आलाकमान के सामने पंजाब की तरह वे ही एक उम्मीद हो सकते हैं। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता, 2023 से पहले भी कोई बड़ा बदलाव हो जाए तो कुछ कह नहीं जा सकता।

पंजाब में कांग्रेस आलाकमान की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद राजस्थान में धमाके के आसार बन रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो जल्द आलाकमान राजस्थान की राजनीति का रूख कर सकता है लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि राजस्थान में राह आसान नहीं होगी। राजस्थान में मंत्रिमण्डल फेरबदल और बड़ी राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं, ऐसे में पार्टी सूत्रों की मानें तो अब जल्द ही राजस्थान में भी आलाकमान की सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है। पंजाब के फैसले के बाद राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने एक पत्रकार के टवीट को रिटवीट किया है। इस टवीट में कहा गया है कि किसी भी राज्य में कोई क्षत्रप अपने दम पर नहीं जीतता है। गांधी-नेहरू परिवार के नाम पर ही गरीब, कमजोर वर्ग और आम आदमी का वोट मिलता है। मगर चाहे वह अमरिन्दर सिंह हो या गहलोत या पहले शीला या कोई और। माकन की ओर से इस टवीट को रिटवीट किये जाने के बाद राजस्थान की राजनीति गरमायी हुई है। माकन के इस टवीट को गहलोत पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं राजनीतिक गलियारों में इस टवीट को पायलट खेमे के लिये बड़ी राहत माना जा रहा है।

पंजाब के फैसले के बाद अब कांग्रेस में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि आलाकमान जल्द ही राजस्थान के गहलोत बनाम पायलट के विवाद को भी सुलझाने का टास्क हाथ में लेगा। पंजाब के बाद अब आलाकमान की नजरें राजस्थान पर टिकी हैं। क्या पंजाब में जिस फॉमूले से कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के विवाद को निपटाया गया है उसी तर्ज पर राजस्थान में भी फैसला लिया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि पंजाब में जिस तरह

से अमरिंदर सिंह की बातों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सिद्धू को कमान दी गई है। अगर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक राजस्थान में भी होती है तो पायलट कैंप की बल्ले बल्ले होनी तय है। कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पंजाब में एक जैसी स्थिति का सामना कर रही है, जहां सचिन पायलट और टी.एस. सिंह देव की क्रमशः मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है। दिल्ली आलाकमान ये नहीं चाहता कि सिंधिया और तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच विवाद के परिणामस्वरूप जो मध्यप्रदेश सरकार गिर गई थी, ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नहीं बने, टिकी है। दिल्ली सियासी गलियारों में चर्चा ये है कि पंजाब के बाद गांधी परिवार और कांग्रेस आलाकमान की नजर दूसरे बड़े क्षत्रप अशोक गहलोत पर है। कांग्रेस हाईकमान की पहली कोशिश है कि पायलट गुट को सत्ता और संगठन में भागीदारी दिलाकर उसका कद और पद बढ़ाया जाए। फिर अगले विधानसभा चुनाव में पायलट की भूमिका तय करने पर विचार कर सकते हैं।

राजस्थान से खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस हाईकमान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज़ है। कहा जा रहा है कि ये खबर सचिन पायलट के लिए काफी चुनाव जीत कर सत्ता में आई। ऐसे में जब 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के चेहरे पर चर्चा होगी तो पायलट गहलोत के सामने चुनौती होंगे। दरअसल, अजय माकन राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हैं। प्रदेश के सियासी मसले को सुलझाना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन, पिछले करीब एक साल में वे इसमें पूरी तरह नाकाम रहे हैं। गहलोत के आगे माकन की दाल नहीं गल पा रही है और माकन द्वारा बार-बार तारीखें देने के बावजूद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और बड़े स्तर की राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं।

इस पर आलाकमान का फोकस है।

क्या कांग्रेस को मिला क्राइसिस मैनेजर?-

सबसे बड़ी बात पंजाब और कांग्रेस की कलह में प्रियंका गांधी ने तारणहार की भूमिका निभाई है। पंजाब में सिद्धू की ताजपोशी में प्रियंका की सक्रियता सभी ने देखी है। वहीं पिछले साल जब राजस्थान में सियासी संकट आया था और पायलट कैंप ने बगावत की थी, उस समय भी प्रियंका गांधी ने दोनों खेमों और आलाकमान के बीच पुल का काम किया था अब राजस्थान में पायलट खेमे की आस और उम्मीद प्रियंका गांधी वाड्रा पर फायदेमंद है और वह इस खबर से काफी उत्साहित भी हैं। पार्टी अब सचिन पायलट को आगे बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस में पंजाब के अमरिन्द्र सिंह और राजस्थान के अशोक गहलोत को सबसे बड़ा क्षत्रप माना जाता है। 2023 में होने वाले राजस्थान विधान सभा चुनावों पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में 2003 और 2013 में दो विधानसभा चुनाव पार्टी ने लड़े थे। दोनों में करारी हार मिली थी। जबकि कांग्रेस पार्टी ने पायलट की अगुवाई में 2018 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और पार्टी

जैसे हालात बन रहे हैं उसके अनुसार आने वाले समय में कांग्रेस आलाकमान द्वारा राजस्थान में जिस प्रकार का भी निर्णय लिया जावेगा। उससे पंजाब की तरह हालात सामान्य होने की उम्मीद नहीं लगती। समन्वय और सामजस्य का समय बहुत पहले ही खत्म किया जा चुका है। अब तलखी बहुत अधिक है, जो बनाने के बजाय बिगाड़ने को अधिक उद्दत करती है। आपसी कलह को और अधिक बढावा मिलेगा। इस कलह का असर राजनेताओं पर कितना होगा कहा नहीं जा सकता लेकिन जनता को राजनीतिक निर्णयों का लाभ नहीं मिल पायेगा।

टीकाकरण: कथनी और करनी में फर्क

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक प्रतियोगिता के कारण एक ओर प्रधानमंत्री की घोषणा के पश्चात आमजनों को इसका लाभ न मिलना है वहीं दूसरी ओर केन्द्र सरकार से निःशुल्क टीके न लेने की मुख्यमंत्री की हठ है। पिछले दिनों शिविरों के माध्यम से कूपन आधारित औसत से भी कम लोगों का टीकाकरण, इन राजनताओं के कथनी और करनी में फर्क को उजागर करता है।

अमित राय

कोरोनाकाल जारी है। कोरोना के हर एक वेरिएंट को दबोचने के लिए टीकाकरण अहम किरदार निभा रहा है। 21 जून 2021 से 18 वर्ष से ऊपर यानि देश के नव युवाओं या मतदाताओं के लिए टीकाकरण निःशुल्क उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी जिसे धरातल पर दिन प्रतिदिन अमल करने का प्रयास जारी है। अन्य निजी केन्द्रों जैसे क्लीनिक, चिकित्सा जांच केंद्रों पर टीका लगवाने के लिए जहाँ विगत दिनों सेवा शुल्क 250 रुपए देने पड़ते थे वहीं 21 जून से मात्र 150 रुपए हो गये हैं। परन्तु उत्तर हावड़ा विधान सभा क्षेत्र इस महामारी काल में भी इन सेवाओं या सुविधाओं से वंचित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक प्रतियोगिता के कारण एक ओर प्रधानमंत्री की घोषणा के पश्चात आमजनों को इसका लाभ न मिलना है वहीं दूसरी ओर केन्द्र सरकार से निःशुल्क टीके न लेने की मुख्यमंत्री की हठ है। पिछले दिनों शिविरों के माध्यम से कूपन आधारित औसत से भी कम लोगों का टीकाकरण, इन राजनताओं के कथनी और करनी में फर्क को

उजागर करता है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में टीकाकरण शिविर बन्द है। जिसका श्रेय एक फर्जी आईएएस देबांजन देव को जाता है। फर्जी आईएएस देबांजन देव ने महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में फर्जी टीकाकरण शिविर लगवाये। इसने सैकड़ों लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया है। बता दें कि फर्जी टीकाकरण के खिलाफ सीबीआइ जांच की मांग को लेकर तीन अलग अलग जनहित याचिका दायर की गयी हैं जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। जगजाहिर है कि आरोपी फर्जी आइएएस की राज्य की सत्तारुढ़ पार्टी तृणमूल काँग्रेस के नेता व मंत्रियों के साथ तस्वीरें भी उजागर हुई थी। वहीं दूसरी ओर फर्जी आईएएस देबांजन देव के सुरक्षा कर्मी के साथ महामहिम राज्यपाल जगदीप धनखड़ की तस्वीर भी अखबार के मुख्य पृष्ठ पर देखा गया है। तृणमूल के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद सुखेन्दु शेखर रॉय ने कुछ ऐसी ही तस्वीरें मीडिया में जारी की और आरोप लगाया कि फर्जी टीकाकरण मामले में राज्यपाल का भी हाथ हो सकता है। हम सभी बखूबी जानते हैं कि दोषारोपण का खेल तो इन राजनीतिक नेताओं का जन्मसिद्ध अधिकार हैं। फर्जी टीकाकरण को लेकर लोगों में बड़ा रोष है।

वर्तमान में पश्चिम बंगाल में टीकाकरण शिविर बन्द है। जिसका श्रेय एक फर्जी आईएएस देबांजन देव को जाता है। फर्जी आईएएस देबांजन देव ने महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में फर्जी टीकाकरण शिविर लगवाया।

जीवन के आस पर मृत्यु को निमंत्रण देने का कुकर्म किया गया है, जो कदापि माफी लायक नहीं है। वहीं हमारे तंत्र की कर्मशैली को उजागर करते हुए आज के डिजिटल इण्डिया में तंत्र की श्रेणी का परिचय भी बता देता है। वैसे कानूनी लीपापोती भी जारी है।

सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो पहला डोज़ टीका लेने के बाद भी परेशान हैं। कोविन की सूची उन्हें दर्शाती है कि उन्होंने आजतक एक भी टीका नहीं लिया है। परेशानी में भागमभाग भी जारी है। दूसरा टीका भी नहीं ले सकते। हाँ दूसरे को पहले के नाम ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं परन्तु यह कदापि उचित नहीं होगा। यहाँ भी तंत्र दोषी है। टीकाकरण के रेकॉर्ड क्यों गायब हैं? 2 से 3 महीने होने जा रहें हैं। लोग राष्ट्र से लेकर ज़िला स्तर तक शिकायत कर प्रशासन व तंत्र को कोस रहे हैं। सुझाव हर जगह से मिला रहा परन्तु समस्या का समाधान नहीं हो रहा। आलम यह है कि कोवैक्सीन के दूसरे डोज़ को लेने की अवधि 28 दिनों से 42 दिनों के अंतराल में हैं, लेकिन लोग अर्धशतक पार कर दूसरे डोज़ से परे पहले डोज़ के नामांकन, ग्रहण पश्चात पंजीकरण के लिए घूम रहे और संदेहास्पद दृष्टि से देख रहे हैं।

पर्यावरण सुरक्षा को बनायें नागरिक धर्म

अवनीश सोमकुवर

विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी नागरिक बंधुओं को शुभकामनाएँ। हम सब अपने पर्यावरण के प्रत्येक तत्व को नमन करें जो सदा से स्पंदनशील हैं। नन्हें पौधे-विशाल वृक्ष, नन्हें झरने-विशाल नदियाँ, नन्हे कंकर-विशाल पर्वत। कीट-पतंगे और मनुष्य। सभी को नमन करने और उनकी उदारता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का दिन है आज।

वैसे पर्यावरण दिवस हर साल मनाते हैं। हर साल कुछ रस्म अदायगी होती है। चिंताएँ जाहिर होती हैं। पर्यावरण के अस्तित्व पर चर्चाएँ होती हैं। चिंता यह है कि पर्यावरण से जुड़े विषय हमारी नागरिक संस्कार से गहरे नहीं जुड पा रहे हैं। चाहे जलवायु परिवर्तन हो या नदियों को शुद्ध और जीवित रखने के मुद्दे हों या पेड़ों को बचाने का मामला हो। हमारा जुडाव गहरा होना चाहिए था।

वर्षो पहले अंग्रेजी के महान प्रकृति प्रेमी कवि विलियम वर्डसवर्थ ने कहा था कि प्रकृति को अपना शिक्षक बनने दो। प्रकृति हमें सिखाती है कि मनुष्य का जीवन हर हाल में खुशहाल बन सकता है। सह-अस्तित्व प्रकृति की सबसे बड़ी सीख है। इमली कभी महुआ से नहीं कहती मेरे सामने क्यों उग आये अपनी पैनी चोंच से पेड़ के मोटे तने में छेद करने वाले कफोड़वे को पेड़ कोई सजा नहीं देता।

> विनाश से बचने के लिये समाज को प्रकृति-आराधना की परंपरा पुनर्जीवित करते हुए वृक्षों के साथ जीना सीखना होगा।

हाल में जर्मन वनस्पति विज्ञानी और अत्यंत प्रतिभाशाली लेखक पीटर होलबेन की किताब दि हिडन लाइफ आफ ट्रीज के कुछ अंश पढ़ने में आये। अब यह साबित हो चुका है कि पेड़ आपस में संवाद करते हैं। उनकी कोई लिपि नहीं होती। वे गंध के माध्यम से अपने संदेशों को एक दूसरे तक

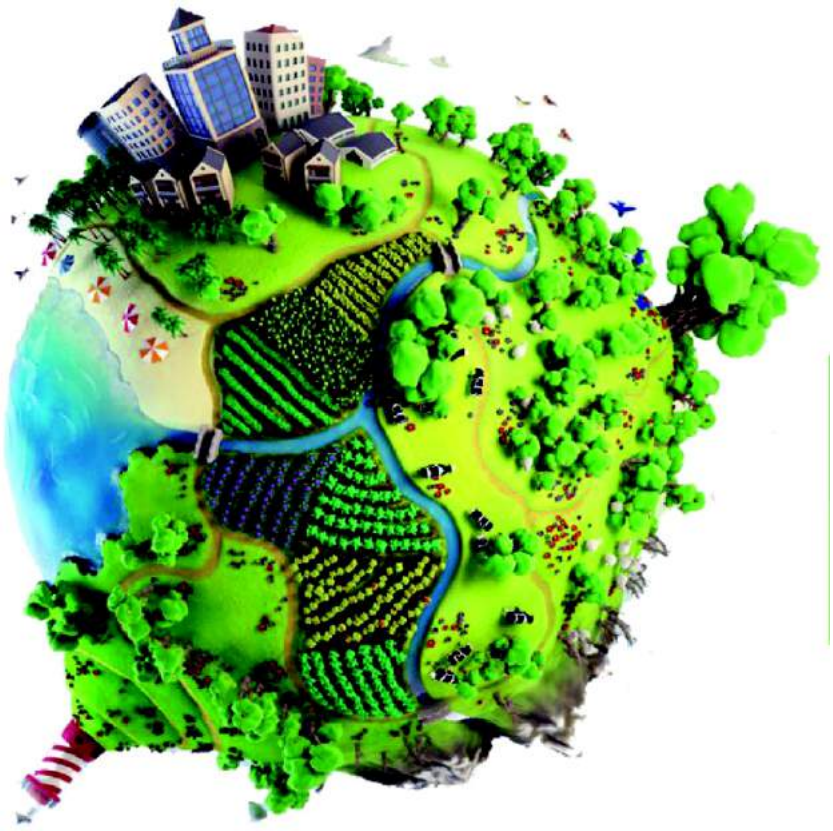

पहुँचाते हैं। वे दुखी होते हैं और खुशियाँ भी मनाते हैं। अनुसंधानों से यह भी सिद्ध हो गया है कि जो पेड़ अपने सजातीय पेड़ों के बीच रहते हैं उनकी आयु लंबी होती है।

हर साल जुलाई का महीना आता है और पर्यावरण बचाने का दिखावा करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ती है। अखबारों में पौधा-रोपण करते हुए चित्र छपते हैं। पौधा-रोपण का समय खत्म होते ही फिर कोई नहीं पूछता कि जिस पौधे को रोपा गया था, वह किस हाल में है। जब पौधों को बचाने की असली जिम्मेदारी आती है, तो साफ बच जाते हैं। इसीलिये जितनी संख्या में पौधे रोपे जाते हैं, बहुत कम जीवित रहते हैं।

हमारी भारतीय संस्कृति में पौधों का रोपण शुभ कार्य माना गया है। भारतीय उपासना पद्धति में वृक्ष पूजनीय है, क्योंकि उन पर देवताओं का वास माना गया है। गौतम बुद्ध का संदेश है कि प्रत्येक मनुष्य को पाँच वर्षो के अंतराल में एक पौधा लगाना चाहिये।

भरत पाराशर स्मृति के अनुसार जो व्यक्ति पीपल, नीम, बरगद और आम के पौधे लगता है और उनका पोषण करता है, उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वृक्षायुर्वेद का उल्लेख है।

वर्तमान समय में पर्यावरण के प्रति जन-चेतना अवश्य बढ़ी है लेकिन महानगरीय समाज पेड़-पौधों के साथ अभी भी आत्मीय संबंध स्थापित नहीं कर पाया है। इतिहास बताता है कि पर्यावरण संवर्धन में यदि भावनात्मक प्रखरता की कमी होती है तो परिणाम नहीं निकलता।

स्वस्थ पर्यावरण की सभी को समान रूप से जरूरत है चाहे वे किसी भी राजनैतिक दल या विचारधारा के हों। ऑक्सीजन के बिना जीवन नहीं होगा।

विनाश से बचने के लिये समाज को प्रकृति-आराधना की परंपरा पुनर्जीवित करते हुए वृक्षों के साथ जीना सीखना होगा।

नई पीढ़ी को नीम, आँवला, पीपल, बरगद, महुआ, आम जैसे परंपरागत वृक्षों की नई पौध तैयार करने की अवधारणा समझाना आवश्यक है। वनस्पतियों का जो सम्मान भारत भूमि पर है वह अन्यत्र नहीं है।

पाश्चात्य विद्वानों, दार्शनिकों ने भी प्रकृति का आदर करना भारतीय धर्मग्रंथों और परंपराओं से ही सीखा है। प्रसिद्ध अमेरिकी निबंधकार और दार्शनिक कवि सर इमर्सन ने अपने शिष्य हेनरी डेविड थोरो को कहा था कि यदि प्रकृति के अलौकिक स्पंदन और माधुर्य को अनुभव करना हो तो उसकी शरण में रहो।

हमारे सभी धार्मिक, सांस्कृतिक संस्कारों में वृक्षों की मंगलमय उपस्थिति है। कई भारतीय संस्कारों, व्रतों, त्यौहारों के माध्यम से वृक्षों की पूजा-अर्चना होती है। वृक्षों के नाम से कई व्रत रखे जाते हैं जैसे वट सावित्री व्रत, केवड़ा तीज, शीतला पूजा, आमला एकादशी, अशोक प्रतिपदा, आम्र पुष्प भक्षण व्रत आदि। मनु स्मृति में वर्णित है कि वृक्षों में चेतना होती है और वे भी वेदना और आनंद का अनुभव करते हैं। समाज के गैर जिम्मेदार व्यवहार से यदि उनकी मृत्यु होती है तो समाज को उतना ही दुःख होना चाहिये जितना प्रियजन की मृत्यु पर स्वाभाविक रूप से होता है।

समाज की ओर से भी पौधा रोपण का स्वैच्छिक अनुष्ठानिक कार्य होना चाहिये। भविष्य की पीढ़ी अपने पुरखों पर गर्व कर सके इसके लिये वर्तमान पीढ़ी से थोड़ी-सी संवेदनशीलता की अपेक्षा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्व-प्रेरणा से हर दिन एक पौधा लगाने का संकल्प लिया है। यह उनके नागरिक संस्कार को प्रोत्साहित और आम नागरिकों को प्रेरित करने की अनूठी पहल है। यदि प्रत्येक नागरिक एक जीवित नन्हे पौधे का जिम्मेदार और संवेदनशील पालक बनने की चुनौती स्वीकार कर लें तो हम सब हरियाली से समृद्ध होते जायेंगे। इसलिये आज यह संकल्प लें कि हम जहाँ रहें अपने पर्यावरण का आदर करें।

सड़कें होगी आत्म-निर्भर
मध्यप्रदेश की रीढ़

गोपाल भार्गव

यूरोप हो या अमेरिका उनके आधुनिक और विकसित नजर आने का पहला अहसास वहाँ की चौड़ी-चौड़ी सड़कें, फ्लाई ओवर और उन पर दौड़ती नजर आती मोटर-कार से आता है। और आए भी क्यों नहीं? ईसा से 2500 वर्ष पुरानी सिन्धु व हड़प्पा सभ्यता हो या फिर मिश्र और मेसोपोटामिया की समृद्धि का मापदण्ड भी वहाँ का आर्किटेक्चर, विकसित सड़कें और मिश्र के पिरामिड के वास्तु-विन्यास को ही माना जाता है। भारत के इतिहास में शेरशाह सूरी जैसे शासक को भी उसके द्वारा तत्कालीन भारत के चढ़गॉव (बांग्लादेश) से वर्तमान काबुल (अफगानिस्तान) के लिए निर्मित वर्तमान जी.टी.रोड (ग्रांड ट्रक रोड) के लिए याद किया जाता है।

पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के समय नार्थ-साउथ कोरिडोर के रूप में देश को आधुनिक विकसित सड़कों से जोड़ने वाले युग का शुभारंभ हुआ। ग्रामीण अंचल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों ने एक तरह से ग्रामों की अर्थ-व्यवस्था को बदल दिया है।

यही कारण है कि मध्यप्रदेश में भी सड़कों के निर्माण, उनके सुदृढ़ीकरण पर राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है। सड़कें विकास की संवाहक है। सड़कों के अभाव में विकास बेमानी हो जाता है। राज्य सरकार द्वारा सड़को के माध्यम से विकास के रथ को गाँव-गाँव तक पहुँचाने का काम व्यापक-दूरदृष्टि के साथ किया जा रहा है। इसकी झलक राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत 2021-22 के बजट में साफ नजर आती है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने चौथे कार्यकाल के पहले वर्ष में आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के सुदृढ़ भवन की जो परिकल्पना की, उसके आधार-भूत चार स्तम्भ में भौतिक अधो-संरचना को प्रथम स्तम्भ के रूप में रखा गया है। प्रदेश की भौतिक अधोसंरचना में सड़कें एक मुख्य घटक हैं। सरकार की सभी सेवाएँ, जन-सुविधाएँ, आम-जन तक तभी पहुँच सकेगी जब प्रदेश में सुदृढ़ आधार-भूत संरचना हो, जिसका पहला पायदान है-सुदृढ़ सड़कें।

वर्तमान में प्रदेश में 8 हजार 858 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके अतिरिक्त 4 हजार 593 किलोमीटर लम्बाई के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए केन्द्र-सरकार से सैद्धान्तिक अनुमति प्राप्त हो गई है। प्रदेश में 11 हजार 389 किलोमीटर राज्य राजमार्ग, 22 हजार 691 किलोमीटर मुख्य जिला मार्ग तथा 28 हजार 023 किलोमीटर अन्य जिला मार्ग है। इस प्रकार कुल 70 हजार 961 किलोमीटर सड़कें शहरी अंचल में तथा लगभग 80 हजार किलोमीटर लंबाई की सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में तैयार की गई हैं। इस तरह यदि हम यह कहें कि मध्यप्रदेश सड़कों के मामले में सबसे धनाढ्य है तो अतिश्योक्ति नहीं होगी।

वर्ष 2020-21 में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद प्रदेश में 2 हजार 500 किलोमीटर सड़कों तथा 13 वृहद पुलों का निर्माण कराया गया, इस पर 3 हजार 522 करोड़ रूपये का व्यय किया गया। इस अवधि में एक हजार 300 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण भी कराया गया। प्रदेश में 540

करोड़ रूपये की लागत से 600 किलोमीटर मुख्य जिला मार्गो के निर्माण उन्नयन का कार्य भी प्रगति पर है। साथ ही नाबार्ड के ऋण और केन्द्रीय सड़क निधि से भी प्रदेश में सड़कों के निर्माण उन्नयन कार्य कराये जा रहे हैं। नाबार्ड मद से 3 हजार 640 करोड़ की लागत से 244 सेतु कार्य स्वीकृत है (44 नग आर.ओ.बी., 7 फ्लाय ओवर तथा 193 वृहद पुल), इनमें से 201 का कार्य प्रगति पर है तथा 9 वृहद पुल और 4 आर.ओ.बी. का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

सुगम यातायात राज्य शासन की प्राथमिकता

मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2021-22 के बजट में लोक निर्माण विभाग को 7 हजार 341 करोड़ रूपये का बजट देने का निर्णय लिया है, जो गत् वित्तीय वर्ष 2020-21 के 6 हजार 866 करोड़ रूपये के बजट से 475 करोड़ रूपये अधिक है। यह सड़कों के निर्माण, सुधार और विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक अप्रैल से शुरू होने वाले इस वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने 2 हजार 441 किलोमीटर नवीन सड़कें, 65 नवीन पुल बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही आगामी तीन वर्षो में 3 हजार 105 करोड़ रूपये की लागत से 105 रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण भारत सरकार की भागीदारी के साथ कराया जाना प्रस्तावित है। जाहिर सी बात है कि इन सड़कों और नये पुल के बनने से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम यातायात के साथ श्रम और समय की बचत होगी।

अति-महत्वाकांक्षी दो परियोजनाएँ

प्रदेश में प्रस्तावित दो अति-महत्वाकांक्षी परियोजनाऐं (1) अटल प्रोग्रेस-वे (2)नर्मदा एक्सप्रेस-वे, पर काम चल रहा है। मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में 358 किलोमीटर लम्बा अटल प्रोग्रेस-वे बनाया जा रहा है। इससे ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के विकास के नये अध्याय की शुरूआत हुई है। इसका विधिवत शिलान्यास केन्द्रीय भू-तल परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा किया जा चुका है। प्रोग्रेस-वे के निर्माण के लिये शासकीय भूमि का आवंटन किया जा चुका है और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन

(डीपीआर) तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार नर्मदा एक्सप्रेस-वे बनाया जाना प्रस्तावित है। इस मार्ग के निर्माण से प्रदेश में पर्यटन, सांस्कृतिक और व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

दुर्घटना प्रतिक्रिया प्रणाली एवं यातायात प्रबंधन केन्द्र

एक तरफ नयी सड़कों और नये पुलों के निर्माण के प्रयास है, तो दूसरी ओर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये भी राज्य सरकार सजग है। राजमार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए से म.प्र. सड़क विकास निगम मुख्यालय में एक्सीडेंट रिस्पांस सिस्टम एवं ट्रेफिक मैनेजमेंट सेंटर बनाया गया है। राजमार्गो पर घटित होने वाली किसी भी दुर्घटना की सूचना कोई भी व्यक्ति 1099 नम्बर पर कॉल-सेंटर को दे सकता है। दुर्घटना की सूचना मिलने पर तत्काल एम्बुलेंस भेजी जाती है, जिससे दुर्घटनाग्रस्त लोगों को निकटस्थ अस्पताल पहुँचाया जा सके और उन्हें त्वरित मेडिकल सहायता मिल सके।

गुणवत्ता पर पैनी-नजर

प्रदेश में सड़कों की गुणवत्ता नियंत्रण करने पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। सड़कों के निर्माण में मुख्य भूमिका डामर की है। राज्य सरकार ने उपयोग से पहले डामर की 12 प्रकार की जाँच और घटिया डामर उपयोग करने पर उसकी आपूर्ति करने वाली कम्पनी को ब्लैक लिस्ट करने जैसे कदम उठाये हैं। जन-शिकायत प्राप्त होने पर विशेषज्ञों से आकस्मिक जाँच कराने का निर्णय सामग्री गुणवत्ता जाँच के लिए 13 चलित मोबाईल प्रयोगशाला के माध्यम से सड़क, पुल निर्माण की गुणवत्ता पर नजर रखने का प्रयास जारी है। इसी क्रम में धीमा कार्य करने वाले ठेकेदारों का पंजीयन निरस्त करना और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई की जायेगी। यह सब सड़क गुणवत्ता के संबंध में सरकार की मंशा स्पष्ट करता है। साथ ही भारत सरकार के आई.ए.एच.ई. के माध्यम से ठेकेदारों और इंजीनियर्स के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

जन-भागीदारी

भारत सरकार की तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार भी सड़कों के रख-रखाव और निर्माण के यूजर-फ्री योजना शुरू करने जा रही है। इनमें टेण्डर प्रक्रिया से 13 चयनित सड़क मार्ग, जिनकी लम्बाई 1098 किलोमीटर है, पर टोल-नाके स्थापित किये जायेंगे। आने-जाने वाले वाहनों से जो टोल टैक्स राशि प्राप्त होगी, उसे सड़क-संधारण पर खर्च कर राज्य सरकार आम-जन की विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना चाह रही है। साथ ही वर्तमान में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग और 24 राज्य राजमार्ग का संचालन बी.ओ.टी. आधार पर किया जा रहा है।

इस पूरी कवायद के पीछे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में मध्यप्रदेश शासन का मुख्य लक्ष्य स्वच्छ, स्वस्थ, सुदृढ़ और सुरक्षित सड़कों के माध्यम से आर्थिक रूप से समृद्ध मध्यप्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

सरोगेसी का कारोबार 30 अरब रुपये सालाना से ज्यादा

देश में लगभग तीन हजार फर्टिलिटी क्लीनिक हैं। सामा ने यह स्टडी संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से की थी। आकांक्षा में भर्ती कई महिलाएं पहले घरेलू काम या मजदूरी या छोटी फैक्टरियों में नौकरी करती थीं। वे सरोगेसी से मिले पैसे से भविष्य संवारने का इरादा रखती हैं। अधिकतर सरोगेट ग्रामीण इलाकों की गरीब महिलाएं हैं।

अर्चना शर्मा

2002 में सरोगेसी को कानूनी वैधता मिलने के बाद देश में हजारों महिलाओं ने दूसरे के लिए बच्चा पैदा कर पैसे कमाए हैं। कारोबार के सरकारी आंकड़े मिलना मुश्किल है। 2012 में सामा रिसोर्स ग्रुप, दिल्ली की एक स्टडी का अनुमान है। भारत में सरोगेसी का कारोबार 30 अरब रुपये सालाना से ज्यादा है। देश में लगभग तीन हजार फर्टिलिटी क्लीनिक हैं। सामा ने यह स्टडी संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से की थी। आकांक्षा में भर्ती कई महिलाएं पहले घरेलू काम या मजदूरी या छोटी फैक्टरियों में नौकरी करती थीं। वे सरोगेसी से मिले पैसे से भविष्य संवारने का इरादा रखती हैं। अधिकतर सरोगेट ग्रामीण इलाकों की गरीब महिलाएं हैं। महामारी में नौकरी गंवाने वाली कई शिक्षित महिलाएं भी आकांक्षा अस्पताल में एग डोनर या सरोगेट के बतौर आ चुकी हैं। फर्टिलिटी क्लीनिक सरोगेटस की तलाश के लिए एजेंटों का इस्तेमाल करती हैं। आकांक्षा अस्पताल की फाउंडर डॉ. नयनतारा पटेल ने 2003 में प्रेक्टिस शुरू की थी। उसके बाद भारत में आणंद शहर

कॉमर्शियल सरोगेसी का प्रमुख केंद्र बन गया। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में रिसर्च और इनोवेशन के लिए आकांक्षा की प्रशंसा हुई है। कुछ महिलाएं सीधे क्लीनिक आती हैं। लेकिन डॉ. पटेल ने 20 केयरटेकर महिलाओं का नेटवर्क बनाया है जो संभावित सरोगेटस की तलाश में मदद करती हैं। सरोगेटस और संतान चाहने वाले पैरेंटस के बीच करार कराने वाले मुंबई के वकील अमित कारखानिस बताते हैं। देश में सरोगेसी इंडस्ट्री के चरम पर हर साल अमेरिका, आस्ट्रेलिया और इजरायल सहित संपन्न देशों से सैकड़ों क्लाइंट आते थे। देश में अधिकतर फर्टिलिटी क्लीनिक सरोगेटस की तलाश के लिए एजेंटों का इस्तेमाल करती हैं। वकील कारखानिस कहते हैं, एजेंसियों या क्लीनिक के लिए कोई कानूनी नियम नहीं हैं। केवल गाइडलाइंस हैं। एजेंट अपने तरीके से काम करते हैं। सरोगेसी इंडस्ट्री विवादों के घेरे में रही है। महिलाओं को हॉस्टल में रखने, कम पैसा देने और सेहत संबंधी जोखिम के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी जाती है।

2014 में एक आस्ट्रेलियाई जोड़े द्वारा एक सरोगेट से जन्मे जुड़वां बच्चों का एक बच्चा नहीं लेने के बाद मामला संसद में उठा था। इसके बाद संसद ने सरोगेसी को केवल भारतीय जोड़ों के लिए सीमित कर दिया था। कारखानिस कहते हैं, मैंने इंडस्ट्री को बढ़ते और नीचे आते देखा है। इंडस्ट्री जब चरम पर थी तब उन्होंने हर साल 200 एग्रीमेंट करवाए थे। हर हफ्ते 15 विदेशी क्लाइंट आते थे। वे इन दिनों साल भर में करीब 20 एग्रीमेंट कराते हैं।

सरोगेसी इंडस्ट्री में गरीब महिलाओं का शोषण- रूस, यूक्रेन और अमेरिका के कुछ राज्यों के समान भारत उन गिने-चुने देशों में शामिल है जहां व्यावसायिक सरोगेसी वैध है। प्रक्रिया से जुड़े नैतिक सवालों के कारण व्यावसायिक सरोगेसी पर पाबंदी लग सकती है। संसद में पेश एक विधेयक में समलैंगिक जोड़ों और अकेली महिला के सरोगेसी से संतान पाने पर रोक लग सकती

है। सांसदों का तर्क है कि इंडस्ट्री गरीब महिलाओं का शोषण करती है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि प्रतिबंध से महिलाओं के गरीबी से बाहर निकलने का एक रास्ता रुक जाएगा। कारोबार चोरी-छिपे चलने लगेगा। डाकोर की 34 वर्षीय सविता वसावा कहती हैं, कॉमर्शियल सरोगेसी पर रोक हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने दूसरी बार अपनी कोख किराए पर देने वाली हैं। वे बेटी के विवाह के लिए पैसा जुटा रही है।

भारत में सरोगेसी- गुजरात का आणंद शहर इस व्यवसाय में अव्व ल है। पिंकी मकवान को चार माह का गर्भ है। उनके पेट में जुड़वां बच्चे पल रहे हैं। पिंकी गुजरात के आणंद शहर में आकांक्षा अस्पताल के बेसमेंट में पिछले चार माह से रह रही हैं। अमूल दूध के लिए मशहूर आणंद को भारत की बेबी फैक्टरी कहा जाने लगा है। एक पुरानी स्टडी के अनुसार देश में सरोगेसी का कारोबार 3 हजार करोड़ रुपये सालाना से अधिक है। इधर, व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध की पहल चल रही है। कुछ माह पहले 24 साल की पिंकी एक गारमेंट फैक्टरी में सात हजार रुपये माह के वेतन पर काम करती थीं। बीस वर्ष की आयु में उनकी शादी पास के गांव में एक सिक्योरिटी गार्ड से हुई थी। लेकिन 2019 में उन्होंने घर छोड़ दिया। वे गारमेंट फैक्टरी में काम करने लगीं। 2020 में कोरोना वायरस महामारी की पहली लहर में लागू सख्त लॉकडाउन के बीच फैक्टरी बंद हो गई। अक्टूबर में पिंकी देश के बड़े सरोगेट अस्पताल आकांक्षा में आ गई। अस्पताल में सरोगेट महिलाओं के एक बच्चे के सफल प्रसव पर किश्तों में लगभग चार लाख 66 हजार रुपए दिए जाते हैं। गर्भपात होने पर महिला को उस तक मिले पैसे के अलावा दस हजार रुपए अतिरिक्त मिलते हैं। जुड़वां बच्चों के कारण पिंकी को लगभग पांच लाख 54 हजार रुपये मिलेंगे। उन्हें एग डोनेशन के लिए 18 हजार रुपये अतिरिक्त मिले हैं।

कोरोना की तीसरी लहर आई तो देश के 10 लाख कुपोषित बच्चे कैसे करेंगे सामना?

स्वदेश शर्मा

देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की चेतावनी बार-बार आ रही है। अभी तक यही माना जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा असर पड़ेगा। ऐसे में एक चिंता की बात ये भी है कि देश में करीब 10 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं और एक्सपर्ट का कहना है कि अगर तीसरी लहर ने बच्चों को प्रभावित किया तो हालात बिगड़ सकते हैं।

कुपोषित बच्चों के संक्रमित होने का खतरा ज्यादा- 29 मई को अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले में 1 साल 4 महीने की बच्ची की कोरोना से मौत हो गई थी। बच्ची को बुखार आया था और 24 मई को उसकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। बच्ची कुपोषित थी। बाद में राज्य सरकार ने इस मौत की जांच के आदेश दिए। इसी तरह पिछले साल नाइजीरिया में एक 8 महीने के बच्चे को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में बच्चे और उसकी मां दोनों ने दम तोड़ दिया था। जब जांच की गई तो सामने आया कि बच्चा और उसकी मां कुपोषण का शिकार थे। इतना ही नहीं, पिछले साल जून में इंडोनेशिया में भी

29 मई को अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले में 1 साल 4 महीने की बच्ची की कोरोना से मौत हो गई थी। बच्ची को बुखार आया था और 24 मई को उसकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।

देशभर में करीब 10 लाख ऐसे बच्चे हैं जो गंभीर रूप से कुपोषित हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया था कि पिछले साल नवंबर तक 9,27,606 बच्चों गंभीर रूप से कुपोषित हैं। इनमें से 3.98 लाख बच्चे यूपी और 2.79 लाख बच्चे बिहार में हैं।

सैकड़ों बच्चों की कोविड-19 से मौत हो गई थी। उस समय हेल्थ एक्सपर्ट ने बच्चों की मौत की वजह कुपोषण को ही माना था। इन सब बातों का जिक्र इसलिए क्योंकि भारत में भी कोरोना की तीसरी लहर आने का अंदेशा सरकार जता चुकी है और अभी तक यही माना जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने की आशंका है। हालांकि, ये तीसरी लहर कितनी खतरनाक होगी, इसको लेकर अभी कोई मोटे तौर पर साफ अनुमान नहीं है। लेकिन जानकार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर भारत में तीसरी लहर आई और बच्चे संक्रमित हुए तो हालात डराने वाले हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि भारत में कुपोषण कम नहीं है। हाल ही में सामने आया था कि देशभर में करीब 10 लाख ऐसे बच्चे हैं जो गंभीर रूप से कुपोषित हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया था कि पिछले साल नवंबर तक 9,27,606 बच्चों गंभीर रूप से कुपोषित हैं। इनमें से 3.98 लाख बच्चे यूपी और 2.79 लाख बच्चे बिहार में हैं।

कुपोषित बच्चों को कोरोना का खतरा ज्यादा- कर्नाटक सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए कुपोषित बच्चों की पहचान करने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। हालांकि, अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं आई है जिसमें इस बात के पुख्ता सबूत मिले हों कि कुपोषित बच्चों को कोरोना का खतरा ज्यादा है। लेकिन सरकार भी इस बात को मानती है कि सामान्य बच्चों की तुलना में कुपोषित बच्चे किसी भी बीमारी या संक्रमण के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं कि अगर कोरोना की तीसरी लहर ने बच्चों को प्रभावित किया तो कुपोषित बच्चों को ज्यादा खतरा होगा। चाइल्ड राइटस पर काम करने वाली संस्था क्राई की को-फाउंडर ईनाक्षी गांगुली ने था कि कोविड से मौत की बड़ी वजह कुपोषण होगी।

साल बदल रहे हैं, लेकिन हालात नहीं- कुपोषण को लेकर पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन भारत में साल बदलने के साथ-साथ हालत नहीं बदल रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 (NFHS-5) का पहला भाग जारी किया था। ये सर्वे 2019-20 में देश के 22 राज्यों में किया गया था। इस सर्वे में सामने आया कि हालात और बिगड़ गए हैं। 2015-16 में NFHS-4 हुआ था, उसकी तुलना में NFHS-5 में पता चला था कि कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ी है। भारत में कुपोषण को तीन पैरामीटर पर मापा जाता है। पहला ये कि 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चों का वजन ऊंचाई के हिसाब से कम है। दूसरा ये कि 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चों का वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम है और तीसरा ये कि 5 साल से कम उम्र के कितने कितने बच्चे ठिगने हैं। NFHS-5 में सामने आया था क जिन 22 राज्यों में सर्वे किया गया था, उनमें से 10 ही ऐसे थे जहां ठिगने बच्चों की संख्या कम हुई थी। 10 राज्य में वेस्टेड बच्चों और 6 राज्यों में अंडरवेट बच्चों की संख्या में सुधार हुआ था। बाकी सभी राज्यों में NFHS-4 की तुलना में बढ़ोतरी ही हुई थी। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में कुपोषण से हालात कितने खराब हैं। एक चिंता की बात ये है कि यूनिसेफ ने भी अनुमान लगाया है कि कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के कारण दुनियाभर में 5 साल से छोटे 67 लाख से ज्यादा बच्चों के कुपोषित होने का खतरा है। हालांकि ये थोड़ी राहत भरी बात है कि भारत में सितंबर तक छोटे बच्चों की कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद भी है।

दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा का गहराता संकट

अली खान

हाल में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड-2021 शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें भोजन के सेवन और कुपोषण पर कोविड-19 महामारी से प्रेरित आय में हानि के प्रभाव का अध्ययन किया है। इसमें दर्शाया गया है कि खाद्य सुरक्षा पर कोविड-19 का प्रभाव विकासशील और अविकसित दुनिया पर अधिक पड़ा हैं। इसके अलावा उन देशों पर खाद्य सुरक्षा का संकट मंडराने लगा है, जिसने महामारी से निपटने में सफलता जरूर अर्जित की लेकिन अन्य जलवायु संबंधी आपदाओं और आर्थिक मंदी के दौर ने बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया की आधे से अधिक कुपोषित आबादी एशिया में पाई जाती है। जबकि एक-तिहाई से अधिक कुपोषित आबादी अफ्रीका में निवास कर रही है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में अफ्रीका में करीबन 46 मिलियन से अधिक, एशिया में 57 मिलियन से अधिक और लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन में करीब 14 मिलियन से अधिक लोग भूख से प्रभावित थे। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट-2021 से साफ जाहिर होता है कि बढ़ती ग़रीबी और घटती आजीविका का प्रभाव खाद्य असुरक्षा

तथा आहार की गुणवत्ता पर पड़ा है।

बता दें कि वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन और भूखमरी की समस्या से निपटने की प्रतिबद्धता जताई गई थी। जिसमें वैश्विक स्तर पर वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों में गरीबी उन्मूलन एसडीजी-1 और भूख एसडीजी-2 को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। मौजूदा हालातों के मध्यनजर 2030 तक गरीबी उन्मूलन और भूखमरी से बड़ी आबादी को बाहर निकालने में कोई बड़ी सफलता हाथ लग जाएगी, ऐसा बिलकुल भी प्रतीत नहीं होता। रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले पांच वर्षो तंक अपरिवर्तित रहने के बाद अल्पपोषण की व्यापकता में महज एक वर्ष के भीतर 1.5 फीसद का इजाफा हुआ है। वहीं 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में लगभग 11.8 करोड़ अधिक लोगों को भूख का सामना करना पड़ा, जो कि करीब 18 फीसद की वृद्धि को दर्शाता है। मौजूदा कोविड-19 संक्रमण के इस दौर में लोगों की आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आय में कमी के कारण भोजन जुटाने के लोगों के सामर्थ्य में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। दुनिया में लगभग तीन में से एक व्यक्ति के पास वर्ष 2020 में पर्याप्त भोजन नहीं था। जहां तक इस आबादी का सवाल है तो

लगभग 3 बिलियन लोगों को भोजन मयस्सर नहीं हो रहा है। यदि हम इसके पीछे बड़े कारणों की बात करें तो खाद्य प्रणालियों को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक और आंतरिक कारक पौष्टिक खाद्य पदार्थो कीं लागत बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते गरीब और मध्यम वर्ग की स्वच्छ भोजन तक पहुंच नहीं बन पा रही हैं। रिपोर्ट से यह तथ्य भी उभरकर सामने आया है कि पुरूषों और महिलाओं के बीच भोजन की पहुंच में काफी अंतर है। जहां वर्ष 2020 में खाद्य-सुरक्षा के मामले में प्रत्येक 10 पुरूषों की अपेक्षा 11 महिलाएं असुरक्षित थीं, जबकि वर्ष 2019 में यह आंकड़ा 10.6 से अधिक था।

अब बड़ा सवाल कि आखिर दुनिया की इतनी बड़ी आबादी को भूखमरी और गरीबी से बाहर कैसे निकाला जाए? दुनिया की बड़ी आबादी को भूखमरी से बाहर निकालने के लिए भागीरथ प्रयासों की सख्त दरकार हैं। इन प्रयासों में सामाजिक सुरक्षा उपायों को

गौरतलब है कि भूखमरी और गरीबी उन्मूलन के लिए पिछले कुछ वर्षो में कंई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री मंत्री किसान सम्मान निधि और सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 योजना चलाई जा रही है। बस जरूरत इस बात की है कि ऐसे प्रयास सतत रूप में किए जाए और जमीनी हकीकत में सामने भी आने चाहिए। तब जाकर कहीं देश की बड़ी आबादी को कुपोषित जीवन और भूखमरी से बाहर निकाला जा सकेगा।

अपनाकर भूखमरी और गरीबी उन्मूलन की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते हैं। सतत विकास और प्रगति के रथ में नितियों का निर्माण इस रूप में किया जाए कि जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को संबल मिलें। जलवायु परिवर्तन और बदलते पारिस्थितिकी मिजाज को भांपते हुए ऐसे प्रयासों को बल दिया जाना चाहिए जिससे कि कमजोर वर्ग के लोगों को मजबूती प्रदान की जा सके। इसके अलावा खाद्य प्रणालियों को दुरुस्त किया जाए। पौष्टिक खाद्य पदार्थो की लागत को कम करने के लिए आपूर्ति श्रंखलाओं में सुधार किया जाए। खाद्य सुरक्षा से संबंधी संरचनात्मक असमानताओं से निपटने के लिए प्रयास करने होंगे ताकि आम आदमी तक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। खाद्य प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिए पूरी दुनिया को एक छत्रच्छाया के नीचे आना होगा, तब जाकर दुनिया से कुपोषण और भूखमरी की समस्याओं से निजात संभव हैं।

जैसा कि मकान, कपड़ा और भोजन ये तीनों मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। मनुष्य अपने जन्म के साथ ही उक्त तीनों मूलभूत आवश्यकताएं महसूस करता आया हैं। मनुष्य अपने स्थाई निवास व सुरक्षा के लिए मकान की आवश्यकता महसूस करता है, साथ ही समाज में रहने के लिए कपड़ों की जरूरत भी समझता है तथा अपने जीवन की तीसरी और महत्वपूर्ण मूलभूत आवश्यकता भोजन के महत्त्व को बखूबी जानता है। भोजन के बिना मनुष्य अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता है। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि भोजन का अभिप्राय अनाज, जल और वह सब कुछ जो खाने योग्य है। भोजन मनुष्य की वह प्राथमिकता है जिससे कि वह सभी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य के लिए आवश्यक भी समझता है। मौजूदा कोविड-19 संक्रमण के इस दौर में बेकारी, भूखमरी और गरीबी में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है। मौजूदा वक्त में कोरोना के कहर के चलते लोगों के रोजगार छिन चुके हैं, परिणामस्वरूप बेकारी बढ़ी है। आइए हम जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? सुरक्षा का अर्थ है मनुष्य की भोजन संबंधी आवश्यकताएं, जो घरेलू मांगों की पूर्ति करती हो साथ ही सस्ती दरों में उपलब्ध भी हो। यदि हम खाद्य सुरक्षा के उन तीन महत्त्वपूर्ण आयामों के बारे में बात करें तो इसमें भोजन की उपलब्धता, भोजन की पहुंच और भोजन का उपयोग को शामिल किया जा सकता हैं। यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारे यहां भोजन की उपलब्धता और

पहुंच को सुनिश्चित करने के पीछे कई सारी दुश्वारियां हैं। जैसे कि हर साल देश के किसी न किसी क्षेत्र में बाढ़ का मुंह बाए खड़े मिलना, इसके अलावा सूखे और अकाल की समस्या भी भोजन की उपलब्धता में दिक्कतें पैदा करती हैं। इसके साथ-साथ लोगों की कमजोर आर्थिक स्थिति भी उनकी खाद्यान्न तक पहुंच के बीच में गहरी खाई का कार्य करती है। वहीं भारत के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और पोषण अवस्था संबंधी रिपोर्ट के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत, दुनिया में सबसे बड़ी खाद्य असुरक्षित आबादी वाला देश बनकर उभरा है। यह रिपोर्ट खाद्य और कृषि संगठन तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुमानित आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2014 से 2019 तक खाद्य असुरक्षित आबादी में 3.8 फिसदी वृद्धि हुई है यानी वर्ष 2014 के मुकाबले वर्ष 2019 तक 6.2 करोड़ अन्य लोग खाद्य असुरक्षित आबादी में शामिल हो गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2014-16 में भारत की 27.8 प्रतिशत आबादी मध्यम और गंभीर ?खाद्य असुरक्षा की चपेट में थी, जबकि वर्ष 2017-19 में यह अनुपात बढ़कर 31.6 प्रतिशत हो गया है। यदि हम खाद्य असुरक्षित आबादी की संख्या की बात करें तो वर्ष 2014-16 में 42.65 करोड़ थी, जबकि अब बढ़कर वर्ष 2017-19 में 48.86 करोड़ हो गई हैं। यहां आबादी के मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा की बात कही गई है। जहां मध्यम स्तरीय खाद्य असुरक्षा से अभिप्राय लोगों की खाद्य तक अनियमित पहुंच से है, जबकि गंभीर स्तरीय खाद्य असुरक्षा से अभिप्राय पर्याप्त मात्रा में भोजन की उपलब्धता न होने या उससे वंचित होने से है। इसी रिपोर्ट के अनुसार, भारत की लगभग 14.8 प्रतिशत आबादी कुपोषित है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2019 में सर्वाधिक कुपोषित लोग भारत में मौजूद थे। भारत में खाद्य सुरक्षा का खतरा मंडराने के साथ-साथ आबादी के कुपोषित होते ग्राफ में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी देखी जा रही है। वर्ष 2018-20 के दरम्यान भारत में कुल

आबादी के बीच कुपोषण का प्रसार 15.3 फीसद था, जो कि इसी अवधि के दौरान वैश्विक औसत 8.9 फीसद की तुलना में काफी खराब प्रदर्शन है। वहीं भारत में वयस्क आबादी में मोटापे के मामले 2012 के 3 फीसद से बढ़कर 2016 में 3.9 फीसद हो गए हैं। इस प्रकार से आंकड़े यही दर्शाते हैं कि भारत की बहुत बड़ी आबादी आज भी कुपोषण का शिकार है और भुखमरी की समस्या से गुजर रही है। आजादी के बाद से ही भारत पर खाद्य-संकट मंडराया हुआ था। भारत में 1960 दशक के अंत तक आते-आते खाद्य संकट अपना विकराल रूप धारण करने लगा।? ऐसे में एक ऐसी क्रांति की आवश्यकता महसूस हुई, जो देश को खाद्य संकट से उबार सके। देश में खाद्य उत्पादन में सुधार के लिए हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ।? इस क्रांति ने भारत को न केवल खाद्य संकट से उबारा बल्कि देश को गेहूं व चावल के निर्यात की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। आज देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात की जा रही है। यदि देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है, तो जरूरी है कि कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए जाए। इसके बिना आत्मनिर्भरता संभव नहीं है। सरकार ने सभी वर्गो तक भोजन की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 1995 में, स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील-योजना 2000 में, गरीबों के लिए अंत्योदय योजना और 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे कई प्रयास किये। जो वाकई सराहनीय है। लेकिन ऐसे लगातार प्रयासों की सख्त दरकार हैं। गौरतलब है कि भूखमरी और गरीबी उन्मूलन के लिए पिछले कुछ वर्षो में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री मंत्री किसान सम्मान निधि और सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 योजना चलाई जा रही है। बस जरूरत इस बात की है कि ऐसे प्रयास सतत रूप में किए जाए और जमीनी हकीकत में सामने भी आने चाहिए। तब जाकर कहीं देश की बड़ी आबादी को कुपोषित जीवन और भूखमरी से बाहर निकाला जा सकेगा।

मौजूदा कोविड-19 के इस दौर में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने आगाह किया है कि विश्व की 7 अरब 80 करोड़ आबादी का पेट भरने के लिए दुनिया में भोजन उपलब्ध है। लेकिन इसके बावजूद 82 करोड़ से अधिक लोग भुखमरी का शिकार है। इस बीच ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस वर्ष कोविड-19 संकट के कारण 4 करोड़ 90 लाख अतिरिक्त लोग अत्यधिक गरीबी का शिकार हो सकते हैं। जो कि वाकई बेहद चिंताजनक है।

अश्लीलता के कारोबार में फिल्मी हस्तियां

प्रमोद भार्गव

पोर्न फिल्में बनाने और उन्हें अनेक सोशल साइट व एपों पर अपलोड करने के मामले में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया है। वे अश्लील फिल्में बनाने, बेचने और इससे धनलाभ कमाने के धंधे में शामिल थे। तीन महिलाओं ने उनके विरुद्ध शिकायत की थी। किराए के बंगले में राज कुंद्रा की कंपनी और उनके सहयोगी फिल्में बनाते थे। उनके साथ रेयान थोरपे एवं उमेश कामत को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को पता चला है कि कुंद्रा की कंपनी आम्र्स प्राइवेट लिमिटेड ने हॉटशाटस एप बनाया और इसे ब्रिटेन में एक रिश्तेदार के नाम से राजिस्टर्ड कंपनी केनरिन को बेच दिया। कुंद्रा का रिश्तेदार प्रदीप बख्शी केनरिन का भागीदार हैं। पुलिस ने दावा किया है कि कुंद्रा के साथ काम करने वाली कुछ लड़कियां अंतरराष्ट्रीय पोर्नोग्राफी गिरोह के शिंकजे में थीं। इस मामले में कुंद्रा को पोर्न फिल्म रैकेट का मुख्य साजिशकर्ता माना है। कुंद्रा की गिरफ्तारी से पता चलता है कि फिल्म, टीवी, सोशल मीडिया और आईटी कंपनियों की अनेक हस्तियां इस नीले कारोबार से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि कुछ समय से एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं।

मोबाइल व कंप्युटर पर इंटरनेट की घातकता का दायरा निरंतर बढ़ रहा है। कुछ समय पहले सीबीआई ने बच्चों के अश्लील वीडियो और फोटो बेचने वाले एक अंतरराष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश किया था। इस मामले में मुंबई के एक टीवी कलाकार को भी गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी के अनुसार आरोपी ने अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशियाई देशों में एक हजार से अधिक लोगों को ग्राहक बनाया हुआ था। वह अश्लील सम्रगी को सोशल साइट इंस्टाग्राम पर भेजकर मोटी कमाई करता था। किशोर बच्चों को अपने जाल में फंसाने के लिए फिल्मी स्टार के रूप में पेश आता था। ये गतिविधियां ऑनलाइल जुड़कर अंजाम तक पहुंचाई जाती थी। सीबीआई ने इसे पास्को एक्ट व अन्य धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया है। दिल्ली में भी इसी प्रकार की घटी एक घटना में 27 किशोर दोस्त सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर एक समूह बनाकर अपने साथ पढ़ने वाली छात्राओं के साथ सामूहिक बलात्कार की षड्यंत्रकारी योजना बना रहे थे। ये सभी दक्षिण दिल्ली के चार-पांच महंगे विद्यालयों में पढ़ते थे। और 11वीं व 12वीं के छात्र होने के साथ अति धनाढय परिवारों से थे। साफ है, स्मार्ट मोबाइल में इंटरनेट और सोशल साइटें बच्चों का चरित्र

खराब करने का बड़ा माध्यम बन रही हैं और इस कारोबार में सेलिब्रिटीज शामिल हैं।

अंतर्जाल की आभासी व मायावी दुनिया से अश्लील सामग्री पर रोक की मांग सबसे पहले इंदौर के जिम्मेबार नागरिक कमलेश वासवानी ने सर्वोच्च न्यायालय से की थी। याचिका में दलील दी गई थी कि इंटरनेट पर अवतरित होने वाली अश्लील वेबसाइटों पर इसलिए प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि ये साइटें स्त्रियों एवं बालकों के साथ यौन दुराचार का कारण तो बन ही रही हैं,सामाजिक कुरूपता बढ़ाने और निकटतम रिश्तों को तार-तार करने की वजह भी बन रही हैं। इंटरनेट पर अश्लील सामग्री को नियंत्रित करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं होने के कारण जहां इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं दर्शक संख्या भी बेतहाशा बढ़ रही है। ऐसे में समाज के प्रति उत्तरदायी सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह अश्लील प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण की ठोस पहल करें। लेकिन पिछले 15 साल से इस समस्या का कोई हल नहीं खोजा जा सका है।

वस्तुस्थिति यह है कि इंटरनेट पर अश्लीलता का तिलिस्म भरा पड़ा है। वह भी दृश्य, श्रव्य और मुद्रित तीनों माध्यमों में। ये साइटें नियंत्रित या बंद इसलिए नहीं होती, क्योंकि सर्वरों के नियंत्रण कक्ष विदेशों में स्थित हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मायावी दुनिया में करीब 20 करोड़ अश्लील वीडियो एवं क्लीपिंग चलायमान हैं, जो एक क्लिक पर कंप्युटर, लैपटॉप, मोबाइल, फेसबुक, ट्यूटर, यूट्यूब और वाटसअप की स्क्रीन पर उभर आती हैं। लेकिन यहां सवाल उठता है कि इंटरनेट पर अश्लीलता की उपलब्धता के यही हालात चीन में भी थे। परंतु चीन ने जब इस यौन हमले से समाज में कुरूपता बढ़ती देखी तो उसके वेब तकनीक से जुड़े अभियतांओं ने एक झटके में सभी वेबसाइटों को प्रतिबंधित कर दिया। गौरतलब है, जो सर्वर चीन में अश्लीलता परोसते हैं, उनके ठिकाने भी चीन से जुदा धरती और आकाश में हैं। तब फिर यह बहाना समझ से परे है कि हमारे इंजीनियर इन साइटों को बंद करने में

क्यों अक्षम साबित हो रहे हैं ? चीन यही नहीं रुका, उसने अब गूगल की तरह अपने सर्च-इंजन बना लिए हैं। जिन पर अश्लील सामग्री अपलोड करना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

इस तथ्य से दो आशंकाएं प्रगट होती हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाब में एक तो हम भारतीय बाजार से इस आभासी दुनिया के कारोबार को हटाना नहीं चाहते, दूसरे इसे इसलिए भी नहीं हटाना चाहते क्योंकि यह कामवद्र्धक दवाओं व उपकरणों और गर्भ निरोधकों की बिक्री बढ़ाने में भी सहायक हो रहा है। जो विदेशी मुद्रा कमाने का जरिया बना हुआ है। कई सालों से हम विदेशी मुद्रा के लिए इतने भूखे नजर आ रहे हैं कि अपने देश के युवाओं के नैतिक पतन और बच्चियों व स्त्रियों के साथ किए जा रहे दुष्कर्म और हत्या की भी परवाह नहीं कर रहे? किसी भी देश के आगे भीख कटोरा लिए खड़े हैं। अमेरिका,जापान और चीन से विदेशी पूंजी निवेश का आग्रह करते समय क्या हम यह शर्त नहीं रख सकते कि हमें अश्लील वेबसाइटें बंद करने की तकनीक और गूगल की तरह अपना सर्च-इंजन बनाने की तकनीक दें? लेकिन दिक्कत व विरोधाभास यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन, कोरिया और जापान इस अश्लील सामग्री के सबसे बड़े निर्माता और निर्यातक देश हैं। लिहाजा वे आसानी से यह तकनीक हमें देने वाले नहीं है। गोया, यह तकनीक हमें ही अपने स्रोतों से विकसित करनी होगी।

ब्रिटेन में सोहो एक ऐसा स्थान हैं, जिसका विकास ही पोर्न वीडियो फिल्मों एवं पोर्न क्लीपिंग के निर्माण के लिए हुआ है। यहां बनने वाली अश्लील फिल्मों के निर्माण में ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने धन का निवेश करती हैं, जो कामोत्तेजक सामग्री, दवाओं व उपकरणों का निर्माण करती हैं। वियाग्रा, वायब्रेटर, कौमार्य झिल्ली, कंडोम, और सैक्सी डॉल के अलावा कामोद्दीपक तेल बनाने वाली ये कंपनियां इन फिल्मों के निर्माण में बढ़ा पूंजी निवेश करके मानसिकता को विकृत कर देने वाले कारोबार को बढ़ावा दे रही हैं। राज कुंद्रा की कंपनी भी ब्रिटेन में पोर्न फिल्में बेच रही थी। यह शहर सैक्स उद्योग के नाम से ही विकसित हुआ है। बाजार को बढ़ावा देने के ऐसे ही उपायों के चलते ग्रीस और स्वीडन जैसे देशों में क्रमशः 89 और 53 फीसदी किशोर निरोध का उपयोग कर रहे हैं। यही वजह है कि बच्चे नाबालिग उम्र में काम-मनोविज्ञान की दृष्टि से परिपक्व हो रहे हैं। 11 साल की बच्ची राजस्वला होने लगी है और 13-14 साल के किशोर कमोत्तेजाना महसूस करने लगे हैं। इस काम-विज्ञान की जिज्ञासा पूर्ति के लिए अब वे फुटपाथी सस्ते साहित्य पर नहीं, इंटरनेट की इन्हीं साइटों पर निर्भर हो गए हैं और उनकी मुट्ठियों में मोबाइल थमाकर हम गर्व का अनुभव कर रहे हैं।

Under Privileged New Shining Stars in Olympics

Samta Pathak

All of us have known and said that the upbringing of a child decides their destiny. This sentence, which was etched in our brains like The Bible has been proved wrong by India's list of Olympic participants for this year. Because of the pandemic, the much awaited Tokyo Olympics was postponed and finally after a year we get to experience the same thrill.

Most out of the 127 participating in the games were

unfamiliar to the word 'parent' let alone parenting because most of them had lost them at a very young age and had thus struggled since childhood for a good cultivation of their own selves.

Alex Antony, a 26 year old lad is a part of the 4x400m mixed relay team. His journey to the Olympics has been nothing but eventful. Antony was born in a fisherman family native to Thiruvana -nthapuram, as a child he was unaware of anything known as physical training, but instead he used to go fishing with his father to build all the strength

and stamina he needed.

Thriving through his own determination, Alex was set out to change his direction and condition of his life, fighting all his difficulties along his path he has set out on his unprecedented sports journey.

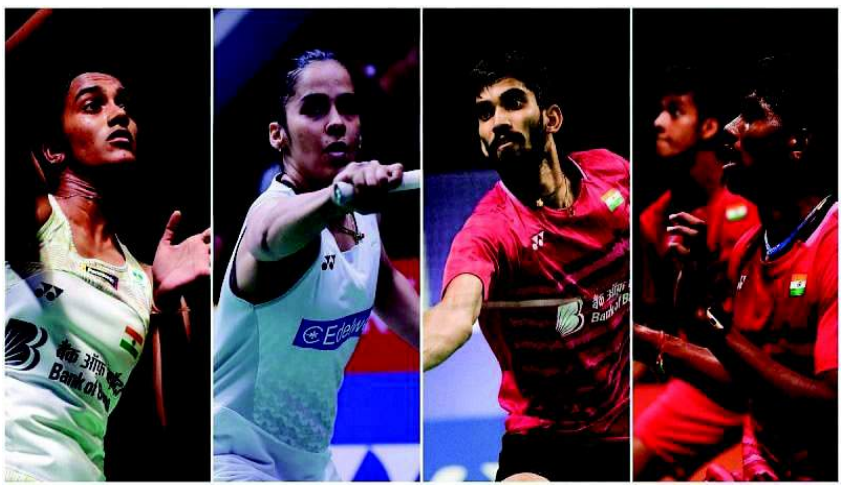

From the mixed relay team like Antony, Revati lost her parents at the tender age of just five years. Revati and her sister were raised by their grandmother. While growing up she did not receive any lessons from her parents, it is only Revati's courage and strength that has brought her to this point where the entire country has their eyes fixated on her.

Simran Jeet Kaur, the lead Indian in boxing has a similar story too. Struggling with deep financial issues, Simran made her journey to the Olympics

based on her own perseverance.

These are just a few from the many stars in our Olympic team who have vowed against defeat. They have made us realise that you do not need only quality parenting to achieve simplicity and purpose, you just need a strong head on your shoulders.

The bottom line being parenting *does not* contribute to anyone's success. All these players coming from trivial parts of the country have proved their presence with their vitality and dedication. Watching these sportsmen achieve great heights, it seems that there is a need to change the proverb "Padhoge likhoge banoge nawab, kheloge kudoge banoge kharab" because the kinship now belongs to those who are winning in the fields, may it be of the Olympics or of life.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

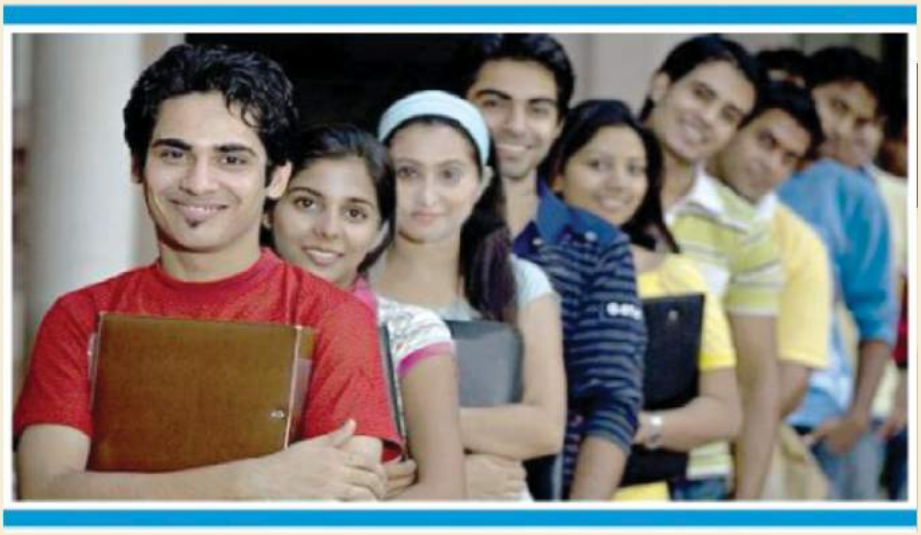

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) 9826064596

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.

SAWARNA COSMETICS

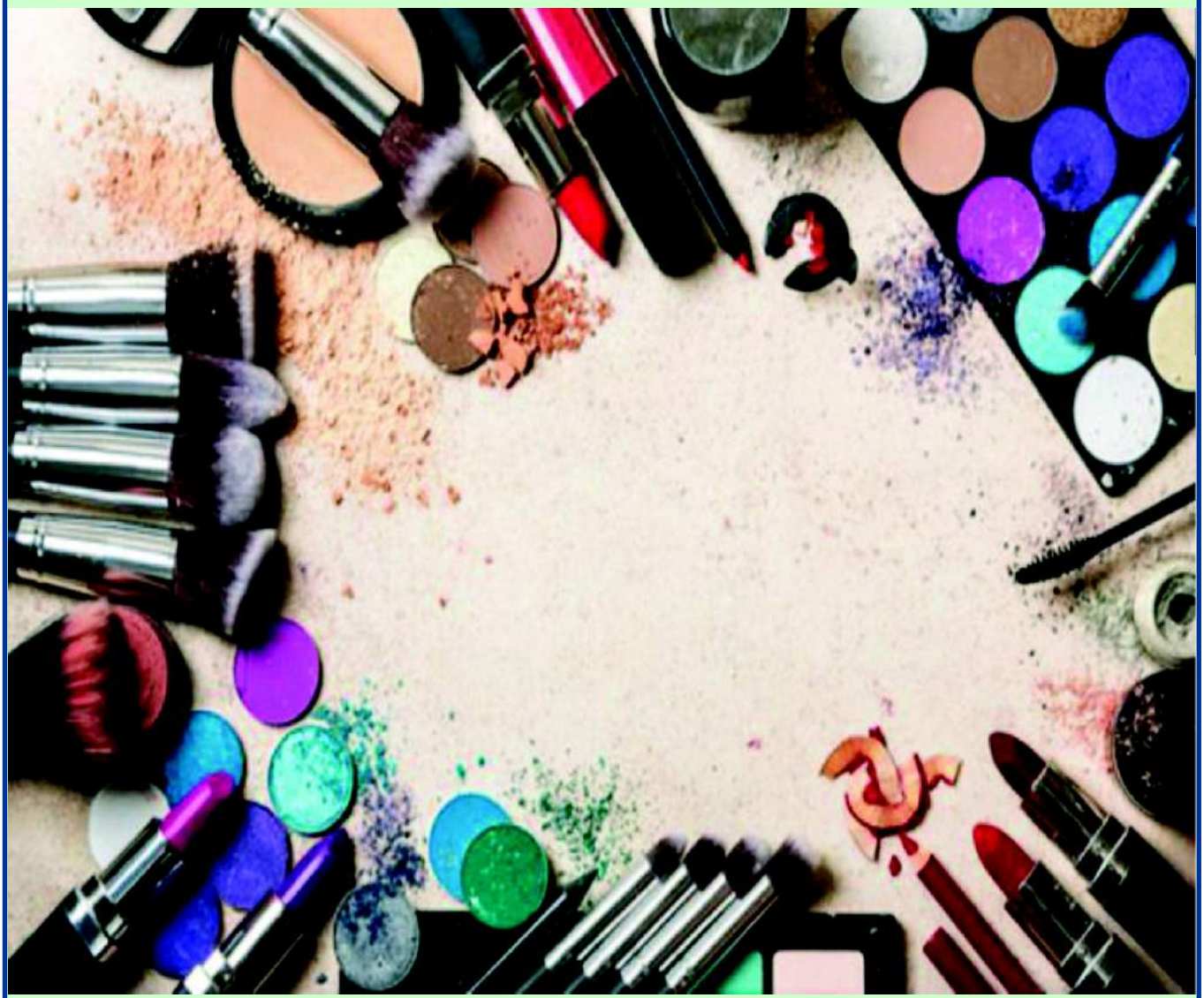

SHOP NO. 101/152, NEW MARKET,
BHOPAL, M.P. 462016

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

मध्यप्रदेश शासन

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

कोविड-19 संक्रमण के दौरान
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए
कल्याणकारी कदम

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना

1 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 के मध्य जो बच्चे इस कोविड आपदा में निराश्रित हो गए हैं, उन्हें योजना में निम्न लाभ दिए जाएंगे -

- रुपए 5000 प्रतिमाह आर्थिक सहयोग।
- निःशुल्क शिक्षा और राशन की व्यवस्था।
- आवश्यकता होने पर सुरक्षित आवासीय सुविधा।
- इस प्रकार की कोई शर्त नहीं कि माता-पिता की मृत्यु कोविड के कारण हुई हो।

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना

- कोविड-19 के कारण शासकीय कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार और सदस्यों को 5 लाख तक की वित्तीय मदद। सभी प्रकार के सरकारी कर्मचारी, संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी इस योजना के पात्र होंगे। यह योजना सभी पीएसयू (सार्वजनिक उपक्रम) और अन्य सरकारी संगठनों पर भी लागू होगी।

मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना

- शासकीय कर्मचारियों की कोरोना के कारण मृत्यु होने पर उनके परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति। यह योजना सभी शासकीय कर्मचारियों सहित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स कर्मचारियों पर भी लागू होगी। साथ ही यह योजना सभी पीएसयू (सार्वजनिक उपक्रम) और अन्य सरकारी संगठनों पर भी लागू होगी।

मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना

- कोविड-19 ड्यूटी पर तैनात फ्रंटलाईन वर्कर की मृत्यु हो जाने पर परिवार को 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान।

मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना

प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर समस्त परिवारों को निःशुल्क कोविड उपचार उपलब्ध कराने के लिए राज्य शासन की योजना -

- प्रदेश के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल एवं कोविड उपचार कराने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कोविड मरीजों को पूर्णतः निःशुल्क उपचार उपलब्ध।
- प्रदेश के 4 बड़े जिलों में 07 निजी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा संचालित अस्पतालों में अनुबंधित बेड पर भर्ती होने वाले कोविड मरीजों को पूर्णतः निःशुल्क उपचार उपलब्ध।
- आयुष्मान कार्डधारी परिवारों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत आयुष्मान संबद्ध निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार उपलब्ध।
- हेल्प लाईन नंबर - 181

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत पात्र परिवारों को 3 माह का मुफ्त खाद्यान्न

- माह अप्रैल, मई एवं जून-2021 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत 4.82 करोड़ पात्र हितग्राहियों को मुफ्त खाद्यान्न का वितरण कराया गया है। साथ ही इन हितग्रहियों को माह मई एवं जून 2021 का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत 10 किलो प्रति हितग्राही मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। विगत माह लगभग 4.00 लाख नवीन हितग्रहियों को जोड़ा गया है एवं यह कार्य निरंतर जारी है।

शहरी पथ विक्रेताओं को वित्तीय सहायता

- शहरी पथ विक्रेता योजना (PM SVANidhi) में नामांकित लगभग 6 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को 1000 रुपए प्रति लाभार्थी के मान से कुल 61 करोड़ रुपये का भुगतान।

ग्रामीण पथ विक्रेताओं को वित्तीय सहायता

- मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में 6 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को 1000 रुपये प्रति लाभार्थी के मान से कुल 61 करोड़ रुपए का भुगतान।

किसानों के लिए

- खरीफ 2020 में लिए गए ऋण के भुगतान की अंतिम तिथि को (शून्य प्रतिशत ब्याज, फसल ऋण योजना अंतर्गत 1 मार्च से 31 मई) भारत सरकार के निर्देशानुसार 30 जून तक आगे बढ़ाया गया।
- गेहूं एवं अन्य फसलों के उपार्जन के माध्यम से किसानों के खाते में 23 हजार 422 करोड़ रुपए का भुगतान।

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता

- मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण श्रमिक कल्याण योजना में अधिसूचित 11.28 लाख श्रमिकों को 1000 रुपए प्रति लाभार्थी के मान से कुल 112.81 करोड़ रुपए की सहायता।

टीकाकरण अवश्य करवाएं | **जिंदगी अनलॉक करें, कोरोना को लॉक करें** | **दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी**

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आकल्पन : मध्यप्रदेश शासन/2021